● वर्ष-3
● अंक-284
रायपुर, रविवार
07 जुलाई 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› रिया के चैप्टर 2 में पहली गेस्ट बनी..

क्या विधानसभा चुनाव में सतीश पुनिया करा पाएंगे पार्टी का बेड़ा पार!

हरियाणा में भाजपा की चुनौतियां

नई दिल्ली.हरियाणा में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने डॉ. सतीश पुनिया और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर को क्रमश: हरियाणा भाजपा का प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किया है। यह घोषणा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा राज्य इकाइयों के लिए प्रभारियों और सह-प्रभारियों की अखिल भारतीय विज्ञप्ति के हिस्से के रूप में की गई थी। सतीश पुनिया, जो पहले राजस्थान के भाजपा अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, त्रिपुरा के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब की जगह लेंगे। इन नियुक्तियों का समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र स्तर पर हालिया मतदान डेटा हरियाणा में प्रतिस्पर्धी दौड़ का सुझाव देता है। यदि आज चुनाव होते हैं, तो डेटा एक विभाजित घर का संकेत देता है, जिसमें विपक्षी इंडिया गुट के प्रमुख गठबंधन के रूप में उभरने की संभावना है। यह भविष्यवाणी 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद आई है, जहां भाजपा के प्रदर्शन में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई थी। पार्टी की सीटों की संख्या 2019 में प्रमुख स्थिति से घटकर हालिया चुनावों में केवल पांच सीटें हासिल कर पाई, जबकि कांग्रेस ने अपनी पांच सीटों के साथ इसकी बराबरी कर ली। इसके अलावा, बीजेपी का वोट शेयर 58.21% से घटकर 46.11% हो गया, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 28.51% से बढ़कर 43.67% हो गया।

विधानसभा क्षेत्रों में, भाजपा ने 90 में से 44 सीटों पर बढ़त बनाई, उसके बाद कांग्रेस 42 सीटों पर आगे रही, और शेष चार सीटों पर आगे रही। न तो जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) और न ही इंडियन नेशनल लोक दल (आईएनएलडी) किसी भी क्षेत्र में आगे रहीं। इससे पता चलता है कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए जरूरी 46 सीटों के बहुमत के आंकड़े से कुछ ही पीछे रह जाएगी। इसके विपरीत, कांग्रेस और आप की संयुक्त संख्या से इंडिया ब्लॉक को साधारण बहुमत मिल जाएगा। हालाँकि, इस बार कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन की कमी ने भाजपा को कुछ राहत दी है।

हरियाणा की राजनीति में जातिगत समीकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो बताता है कि क्यों प्रमुख दावेदार चुनावों से पहले उन्हें संतुलित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हरियाणा में, ओबीसी मतदाताओं का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 30% है, इसके बाद जाट लगभग 25% और अनुसूचित जाति (एससी) लगभग 20% हैं। ओबीसी समुदाय पर प्रभावी ढंग से निशाना साधने के लिए बीजेपी ने हरियाणा चुनाव के लिए सतीश पुनिया को सह-प्रभारी नियुक्त किया है। जैसे-जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, पार्टी की रणनीति को आकार देने और जमीन पर क्रियान्वयन में पुनिया और नागर की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

आज जगन्नाथ रथ यात्रा

10 लाख से ज्यादा पहुंचेंगे श्रद्धालु

पुरी। आषाढ़ मास की द्वितीया को होने वाले इस श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के भव्य आयोजन में देश-विदेश से 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने के अनुमान है। वहीं श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर पहुंच चुकी हैं। इस ऐतिहासिक यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस ने चौक-चौबंद व्यवस्था की है। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है।

एडीजी (कानून व्यवस्था) संजय कुमार के हवाले से कहा गया है कि पुलिस पहली बार एआई कैमरों और ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। इससे भीड़ का पता लगाने, वाहन की गिनती करने और सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की दिशा में मदद मिलेगी। इसके अलावा, रैपिड एक्शन फोर्स की तीन कंपनियां, सीआरपीएफ की दो कंपनियां और एसओजी ग्रुप की आठ प्लाटून हर कदम पर यात्रा के साथ होंगी। उधर, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव और प्रवती परिदा के साथ शनिवार को रथ यात्रा की शुरुआत से पहले पुरी में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। सोशल मीडिया में इसकी तस्वीरें साझा करते हुए सीएम माझी ने कहा, पवित्र रथ यात्रा से पहले पुरी लाडा दंड में आयोजित स्वच्छ भारत अभियान में शामिल होकर मैं खुद को धन्य महसूस कर रहा हूं। कल (रविवार को) भगवान श्रीजगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा बड़दाना के रत्नजटित सिंहासन से निकलकर बड़दांड में लाखों भक्तों को सीधे दर्शन देंगे।

केजरीवाल को नहीं मिली राहत, पत्नी सुनीता ने लगाए आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने शनिवार को सुनीता केजरीवाल को दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत के दौरान उनकी चिकित्सा स्थिति की निगरानी के लिए एम्स द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के साथ उनके पति अरविंद केजरीवाल के परामर्श के दौरान उपस्थित होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हालाँकि, अदालत ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री को मेडिकल बोर्ड के साथ उनके परामर्श के मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

शहर की अदालत ने सुनीता केजरीवाल को केजरीवाल को निर्धारित आहार से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए स्वतंत्र रूप से मेडिकल बोर्ड से संपर्क करने की अनुमति दी।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। मामले के सिलसिले में सीबीआई ने 26 जून को आप संयोजक को गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिन में सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश में आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक एक गहरी साजिश का शिकार थे और एक गवाह के झूठे बयान पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि ईडी ने टीडीपी सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी (एमएसआर) के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। तेलुगु देशम पार्टी सत्तारूढ़ एनडीए की घटक है।

भाजपा का पलटवार

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सुनीता केजरीवाल वास्तव में आम आदमी पार्टी की स्टार मैनिपुलेटर बन गई हैं क्योंकि समय के साथ उन्होंने कहानी सुनाने की कला में महारत हासिल कर ली है जैसे उनके पति अरविंद केजरीवाल और अन्य पार्टी सहयोगियों ने किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि यह एक मुख्यमंत्री की पत्नी द्वारा जारी किया गया वीडियो है जो स्वयं वरिष्ठ सरकारी अधिकारी रह चुकी हैं। यह आश्चर्यजनक है कि वह न्यायपालिका पर संदेह कर रही हैं क्योंकि अपनी कहानी सुनाने के दौरान वह बार-बार कहती हैं कि अदालत ने तीन बार सांसद श्री एम.एस. रेड्डी के बेटे को जमानत देने से इनकार कर दिया जब उसने बार-बार अपना मूल सत्य बयान दिया लेकिन 2023 में श्री एम.एस. रेड्डी पारिवारिक दबाव के कारण झुक गए और बयान बदल दिया जिसके बाद रेड्डी के बेटे को अदालत ने जमानत दे दी।

तिहाड़ में बंद सत्येंद्र जैन की बढ़ीं मुश्किलें!

उपराज्यपाल (एलजी) ने रिश्वत मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक (पीओसी) अधिनियम के तहत जांच को शनिवार को मंजूरी दे दी। जैन पर 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने के 571 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के सिलसिले में 7 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। उपराज्यपाल जैन के खिलाफ एसीबी द्वारा जांच की मंजूरी के लिए पीओसी अधिनियम, 1998 की धारा 17ए के तहत मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने के डीओवी के प्रस्ताव से सहमत हुए। जैन, आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे और परियोजना के नोडल प्राधिकारी थे, पर 1.4 स्थापित करने में देरी के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पर लगाए गए 16 करोड़ रुपये के जुर्माने को माफ करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है।

बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव, भाजपा-तृणमूल आमने-सामने

कोलकाता। 10 जुलाई को पश्चिम बंगाल में चार विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में भाजपा का सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से मुकाबला होगा। मानिकतला, रायगंज, राणाघाट दक्षिण और बागदाह विधानसभा क्षेत्रों में 10 जुलाई को उपचुनाव होने जा रहे हैं। इनमें से तीन विधानसभा क्षेत्रों- रायगंज, राणाघाट दक्षिण और बागदाह में भाजपा विधायकों ने पार्टी बदल ली और टीएमसी में शामिल हो गए और हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में हार गए। विधानसभा क्षेत्र मानिकतला, पारंपरिक रूप से कांग्रेस की सीट है, जिसे हाल के चुनावों में टीएमसी के गढ़ के रूप में देखा गया था। हालांकि, पांडे की मृत्यु के महीनों बाद भी इस सीट पर उपचुनाव नहीं हो सका, क्योंकि भाजपा उम्मीदवार कल्याण चौबे ने मतदान में अनियमितता का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। 2021 के चुनावों के दौरान और वोटों की दोबारा गिनती की मांग की। कानून उस सीट के लिए तब तक कोई भी चुनाव कराने से मना करता है जब तक कि उस सीट से संबंधित किसी भी चुनाव याचिका का अदालत में समाधान नहीं हो जाता। 29 अप्रैल, 2024 को चौबे ने अदालत से अपनी चुनाव याचिका वापस ले ली, जिससे इस सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया। टीएमसी ने इस सीट पर साधन पांडे की पत्नी सुप्ति पांडे को बीजेपी के कल्याण चौबे के खिलाफ मैदान में उतारा है, जिन्होंने पहले 2021 में साधन पांडे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। 2021 में भाजपा ने रायगंज विधानसभा सीट जीती थी, लेकिन पार्टी विधायक कृष्णा कल्याणी टीएमसी में शामिल हो गईं। उन्हें रायगंज से संसदीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया था, लेकिन वह भाजपा उम्मीदवार कार्तिक पॉल से लोकसभा चुनाव हार गए।

प्रमुख समाचार

कुलगाम में दो मुठभेड़, चार आतंकी ढेर; एक जवान शहीद

जम्मू कश्मीर। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के मोदेरगाम गांव में संयुक्त बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में चार आतंकियों के ढेर होने की खबर है। वहीं, एक जवान बलिदान हो गया और एक जवान घायल है। घायल जवान को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, कुलगाम के इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया इनपुट मिला था। इसके बाद सुरक्षाबलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान सेना के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। वहीं, इसके करीब दो घंटे बाद कुलगाम जिले के ही फ्रिसल चिन्निगम क्षेत्र में मुठभेड़ शुरू हुई, जहां पुलिस और सुरक्षा बल आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं।

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने की चिदंबरम के बयान की निंदा

तिरुवनंतपुरम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की उस टिप्पणी की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि तीन नए आपराधिक कानूनों का मसौदा अंशकालिक (पार्ट-टाइमर) लोगों ने तैयार किया था। धनखड़ ने कहा, सुबह जब एक राष्ट्रीय दैनिक में चिदंबरम के साक्षात्कार को पढ़ा तो मैं शब्दों से परे चौंक गया। धनखड़ ने कहा, क्या हम संसद में पार्ट-टाइमर हैं? यह संसद की बुद्धिमता का अक्षम्य अपमान है। उन्होंने कहा, इस तरह की कहानी (नैरेटिव) को आगे बढ़ाया जा रहा है और एक सांसद को पार्ट-टाइमर के रूप में लेबल किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा, मैं उनसे (चिदंबरम) अपील करता हूं कि कृपया सांसदों के बारे में अपमानजनक और बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी वापस लें। धनखड़ भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, जब जानकार दिमाग जानबूझकर आपको भटकाते हैं, तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है।

कोरोना काल में 'फरिश्ते' बने हजारों संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना महामारी के समय कोरोना पीड़ितों के लिये 'फरिश्ते' साबित होने वाले अपने करीब पांच हजार संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। पिछले महीने 30 जून के बाद इन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया गया और कई जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों ने इनसे कार्य न लेने का आदेश भी जारी कर दिये हैं। ऐसे में कोविड काल में जान-जोखिम में डालकर रोगियों की सेवा करने वाले यह संविदा कर्मचारी निराश और गुस्से में हैं। संविदा कर्मियों का कहना है कि यह सरकार की हिटलरशाही है। कोरोना महामारी के समय हमने अपने जान की परवाह नहीं करते हुए अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया जिसकी सजा हमें नौकरी से निकाल कर दी गई है। अब सरकारी फरमान के खिलाफ संविदा कर्मी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। गौरतलब हो, कोरोना महामारी के समय रोगियों की जांच व उपचार के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), उत्तर प्रदेश ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, कंप्यूटर आपरेटर, आयुष चिकित्सक और नान मेडिकल साइंटिस्ट इत्यादि के पदों पर संविदा पर सात हजार लोगों की भर्ती की थी।

देश को पहला लाइट टैंक का हजीरा में शुरू किया परीक्षण

नई दिल्ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्राधिकरण (डीआरडीओ) ने शनिवार को गुजरात के हजीरा में अपने हल्के युद्धक टैंक जोरावर का परीक्षण शुरू किया। डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित, ज़ोरावर को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पार चीनी तैनाती के खिलाफ पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। रूस-यूक्रेन संघर्ष के मद्देनजर, यूएवी और आवारा गोला-बारूद को टैंकों में एकीकृत किया गया है। 25 टन का ज़ोरावर पहला टैंक है जिसे दो साल के रिकॉर्ड समय में डिजाइन और परीक्षण के लिए तैयार किया गया है। अपनी उभयचर क्षमताओं के साथ, हल्का टैंक पहाड़ों में खड़ी चढ़ाई पार कर सकता है और भारी वजन वाले टी-72 और टी-90 टैंकों जैसे अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक आसानी से नदियों और अन्य जल निकायों को पार कर सकता है। इस टैंक का नाम 19वीं सदी के डोगरा जनरल ज़ोरावर सिंह के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में सशस्त्र अभियानों का नेतृत्व किया था।

स्टार्मर के नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक

लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने शनिवार को नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अपने मंत्रियों के लिए मिशन डिलीवरी बोर्ड बनाए, ताकि वह बदलाव लागू किए जा सकें जिनके लिए जनता ने आम चुनाव में मतदान किया था। स्टार्मर ने बैठक के बाद के 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रधानमंत्री के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश को बताया कि वह लेबर पार्टी की नई सरकार के लिए तय लक्ष्यों को कैसे पूरा करना चाहते हैं। जिसमें टूटी हुई राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) को ठीक करना भी शामिल है। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने पूरे मंत्रिमंडल को याद दिलाया कि हमें शब्दों से नहीं, बल्कि काम से आंका जाएगा। उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल की बैठक में मैंने इस बात पर भी चर्चा की कि हमने अपने घोषणापत्र में जो वादे किए हैं, उन्हें हम कैसे अमलीजामा पहनाएंगे। हमें जिस बदलाव की जरूरत होगी, उसे पूरा करने करने के लिए हमारे पास मिशन डिलीवरी बोर्ड होंगे। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए उन बोर्डों की अध्यक्षता करूंगा कि यह सभी को पता हो कि वे सरकार में मेरी प्राथमिकताएं हैं।

कीर्ति-शौर्य चक्र जाबांजों की कहानी

अंधाधुंध फायरिंग तो कहीं हैंड ग्रेनेड, रणबांकुरों ने दिया करारा जवाब

जितेंद्र भारद्वाज

नक्सल और आतंकवाद विरोधी अभियानों में देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल %सीआरपीएफ% के जांबाजों ने असाधारण वीरता का परिचय दिया है। कहीं छिपकर दुश्मन ने सीआरपीएफ दस्ते पर अंधाधुंध फायरिंग की, तो कहीं हैंड ग्रेनेड बरसा कर जवानों का उत्साह कम करने का प्रयास किया। सीआरपीएफ के रणबांकुरों ने आतंकियों और नक्सलियों को करारा जवाब दिया। उन्हें मार गिराया। भीष्ण मुठभेड़ में सीआरपीएफ के कई शूरवीरों ने अपना बलिदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को इन्हीं वीरों को कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र देकर सम्मानित किया है। सीआरपीएफ के चार जांबाजों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जबकि दो वीरों को शौर्य चक्र से नवाजा गया है।

ये है वीरता की गौरवगाथा

सीआरपीएफ, आतंकवाद और नक्सल प्रभावित इलाकों में लंबे समय से तैनात है। विभिन्न जोखिम भरे अभियानों में इस बल के शूरवीरों ने असाधारण वीरता का परिचय दिया है। सीआरपीएफ के छह बहादुरों को औरंगाबाद %बिहार%, श्रीनगर %जेएंडके% और बीजापुर %छत्तीसगढ़% में अभियानों के दौरान उनकी जांबाजी के लिए सम्मानित किया गया है। 3 अप्रैल 2021 को बीजापुर में माओवादियों के खिलाफ लड़ाई में उनकी वीरता के लिए चार सीआरपीएफ बहादुरों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। उस दिन, बीजापुर जिले के थाना तर्रेम के सिलगेर वन क्षेत्र में 210 कोबरा, 241 बटालियन सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा एक संयुक्त माओवादी विरोधी अभियान संचालित गया था। अभियान में तब गंभीर मोड़ आ गया जब माओवादियों ने जवानों पर घात लगाकर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। भारी मात्रा में हैंड ग्रेनेड से हमला कर दिया।

छह घंटे तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी

यह अभियान बेहर खतरनाक था। घने जंगल में प्रतिकूल और खतरनाक स्थिति के बावजूद, जवानों ने असाधारण साहस का प्रदर्शन किया। शुरुआती हमले का मुकाबला करते हुए जवानों ने दृढ़ संकल्प के साथ जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने छह घंटे तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी। माओवादियों को भारी नुकसान पहुंचाया। नतीजा, माओवादियों को अंतत: घटनास्थल से भागना पड़ा। इस भीषण मुठभेड़ में 210 कोबरा के सात और 241 बटालियन के एक जवान सहित कुल 22 रणबांकुरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इनमें से चार बहादुरों-शहीद इंस्पेक्टर दिलीप कुमार दास, शहीद हेड कॉन्स्टेबल राज कुमार यादव, शहीद कॉन्स्टेबल बबलू राभा और शहीद कॉन्स्टेबल शंभु रॉय को उनकी असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति

द्रौपदी मुर्मू ने चारों शहीदों के परिजनों को कीर्ति चक्र प्रदान किया है। शहीद इंस्पेक्टर दिलीप कुमार दास की पत्नी वीर नारी प्रांजलि दास, शहीद हेड कांस्टेबल राज कुमार यादव की पत्नी वीर नारी ज्ञानमती यादव, शहीद कांस्टेबल बबलू राभा की पत्नी वीर नारी लिपिका राभा व उनकी मां कल्याणी राभा और शहीद कांस्टेबल शंभु रॉय की मां अंजुली रॉय ने कीर्ति चक्र प्राप्त किया।

बायां पैर खोने के बावजूद मोर्चे पर डटे रहे

25 फरवरी 2022 को चकरबंधा वन क्षेत्र, थाना मदनपुर, जिला औरंगाबाद में नक्सलियों के विरुद्ध तलाशी अभियान संचालित किया गया था। इसमें सीआरपीएफ की 205 कोबरा व 47 बटालियन और बिहार पुलिस शामिल थी। अभियान के दौरान, जैसे ही जवान अपने लक्ष्य के पास पहुंचे, माओवादियों ने जवानों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। अटूट दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए, सहायक कमांडेंट बिभोर कुमार सिंह ने हमले की कमान संभाली। भीषण गोलीबारी के बीच नक्सलियों ने आईईडी का इस्तेमाल किया। सीआरपीएफ दस्ते ने नक्सलियों को करारा जवाब दिया। नतीजा, माओवादी पीछे हट गए। आईईडी विस्फोट में अपना बायां पैर खोने तथा गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, बिभोर कुमार सिंह अपने जवानों का नेतृत्व करना जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप नक्सलियों के हाइड आउट पर कब्जा कर लिया। आईईडी बनाने की सामग्री बरामद की। मुठभेड़ में असाधारण बहादुरी, अदम्य इच्छाशक्ति तथा अद्वितीय रणकौशल के लिए सहायक कमांडेंट बिभोर कुमार सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है।

घर में छिपे आतंकवादी से हाथापाई

19 दिसंबर 2021 को, दरबाग क्षेत्र, थाना हरवान में सीआरपीएफ की वैली क्यूएटी, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से आतंकवाद विरोधी अभियान संचालित किया गया था। खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एक घर में छिपे आतंकवादी को मार गिराने के लिए एक हाउस इंटरवेंशन टीम का गठन किया गया। अभियान के दौरान कांस्टेबल गामित मुकेश कुमार और उनके साथी ने घर में छिपे आतंकवादी से हाथापाई की। उसे घर से बाहर निकलने के लिए विवश कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच, कांस्टेबल गामित मुकेश कुमार ने अतुलनीय साहस और रणकौशल का प्रदर्शन करते हुए अंतत: आतंकवादी को मार गिराया। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया। अदम्य साहस, रणकौशल एवं दृढ़ता के लिए कांस्टेबल गामित मुकेश कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है।

सम्पूर्णता अभियान के तहत क्षेत्र का होगा विकास: नेताम

कृषि मंत्री ने शंकरगढ़ में किया संपूर्णता अभियान की शुरूआत

बलरामपुर। शंकरगढ़ में संपूर्णता अभियान की शुरूआत करते हुए आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि अभियान के तहत शंकरगढ़ क्षेत्र और यहां की जनता के चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। अधोसंरचनाओं के निर्माण, आर्थिक गतिविधियों का उन्मुखीकरण और विभिन्न विकास कार्यों के माध्यम से समाज की उन्नति के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा।

मंत्री श्री नेताम ने बताया कि देशभर के चिन्हित 100 आकांक्षी विकासखण्डों का चयन अभियान के तहत किया गया है, जहां शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन विभागों के समन्वय से किया जाएगा। आगामी तीन महीने में अभियान का क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा और बिजली, पेयजल, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य कई योजनाओं का लाभ क्षेत्र के नागरिकों को मिलने लगेगा। महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाएगा। कार्यक्रम में सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज और सामरी विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा विशेष रूप से उपस्थित थे।

कार्यक्रम में उपस्थित सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने आकांक्षी ब्लॉक परियोजना के तहत् सम्पूर्णता अभियान के शुभारंभ होने पर उपस्थित लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आकांक्षी ब्लॉक के संपूर्णता अभियान के सभी मानकों को सभी की सहभागिता से पूर्ण किया जाना है। इस अभियान के तहत् महिलाओं में आर्थिक संबलता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करायी जाएगी। सामरी विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा ने भी

कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर जिले के कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का तथा पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती रेना जमील तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

ज्ञातव्य है कि आकांक्षी विकासखण्ड, वे विकासखण्ड हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं। ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए नीति आयोग द्वारा 04 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 03 महीने का संपूर्णता अभियान आरंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य देश भर के आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में 06 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। इस सम्पूर्णता अभियान के तहत देश के सभी आकांक्षी ब्लॉकों में 06 चिन्हित केपीआई पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अंतर्गत पहली त्रैमासिक अवधि के दौरान प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, ब्लॉक में लक्षित जनसंख्या के मुकाबले मधुमेह की जांच कराने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, ब्लॉक में लक्षित जनसंख्या के मुकाबले उच्च रक्तचाप के लिए जांचे गए व्यक्तियों का प्रतिशत, आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, मृदा नमूना संग्रहण लक्ष्य के मुकाबले सृजित मृदा स्वास्थ्य कार्डों का प्रतिशत तथा ब्लॉक में कुल स्वयं सहायता समूहों के मुकाबले रिवाल्विंग फंड प्राप्त करने वाले स्व-सहायता समूहों का प्रतिशत शामिल है।

आकांक्षी विकासखण्डों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रारंभ की गई संपूर्णता अभियान के तहत बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखण्ड में अभियान की शुरूआत के दौरान आदिम जाति कल्याण व कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने उपस्थित अतिथियों, गणमान्य नागरिकों, अधिकारी-कर्मचारियों, स्कूली बच्चों सहित आमनागरिकों को संपूर्णता अभियान को सफल बनाने के लिए सहभागिता निभाने और अभियान को सफल बनाने की शपथ दिलाई।

मशाल जलाकर मशाल यात्रा का किया गया शुभारंभ

मंत्री श्री नेताम व उपस्थित अतिथियों ने मशाल जलाकर कलेक्टर को सौंपा। मशाल का उद्देश्य समुदाय के बीच जागरूकता लाना और लोगों को अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। यह मशाल संपूर्णता अभियान कि शुरूआत को एक नई उर्जा और उत्साह प्रदान करेगा। जिससे ग्रामीण समुदाय के लोग जागरूकता के साथ-साथ समग्र विकास के मुख्य धारा से जुड़ पायेंगे।

सुरक्षाबलों को निशाना बनाने के लिए आईईडी लगाने जा रहे सात नक्सली गिरफ्तार

सुकमा। सुकमा में लगातार नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बार फिर से सुकमा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों को निशाना बनाने की फिराक में आईईडी लगाने जा रहे सात नक्सलियों को घेराबंदी कर जवानों ने गिरफ्तार किया है। मामले की पुष्टि करते हुए सुकमा एसपी किरण चौहान ने बताया कि थाना चिंतलनार क्षेत्र से 07 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में मिली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गिरफ्तार नक्सलियों से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया। गिरफ्तार सभी नक्सली थाना चिंतलनार क्षेत्र के है निवासी।

बता दें कि सुकमा जिले में नक्सलियों के खिलाफ नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में पुलिस को ये सफलता मिली है। पकड़े गये संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने पर अपना नाम कमश: 01. कुहराम भीमा पिता हुंगा उम्र-लगभग 24 वर्ष निवासी सुरपनगुड़ा, नीलापारा, थाना चिंतलनार, 02. हेमला गुड्डी पिता स्व. नंदा उम्र-लगभग 20 वर्ष निवासी सुरपनगुड़ा, एर्रापारा, थाना चिंतलनार, 03. मिड़ियम गंगा पिता मल्ला उम्र-लगभग 27 वर्ष निवासी सुरपनगुड़ा, नीलापारा, थाना चिंतलनार, 04. सुण्डाम भीमा पिता लखमा उम्र- लगभग 37 वर्ष निवासी सुरपनगुड़ा, एर्रापारा, थाना चिंतलनार, 05. माड़वी जोगा पिता हांदा उम्र-लगभग 22 वर्ष निवासी सुरपनगुड़ा, एर्रापारा, थाना चिंतलनार,06. नुप्पो मंगा पिता गंगा उम्र-लगभग 37 वर्ष निवासी सुरपनगुड़ा,

एर्रापारा, थाना चिंतलनार, 07. हेमला नंदा पिता स्व. हिड़मा उम्र-लगभग 21 वर्ष निवासी सुरपनगुड़ा, नीलापारा, थाना चिंतलनार का होना तथा सभी नक्सल संगठन में सुरपनगुड़ा आरपीसी अंतर्गत मिलिशिया सदस्य के पद पर कार्य करना बताये।

पकड़े गये संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा रखे गये थैले की चेकिंग करने से क्रमश:- 01.कुहराम भीमा के कब्जे के थैले से देशी बी.जी.एल सेल 02 नग, 02. हेमला गुड्डी के कब्जे के थैले से 01 नग बी.जी.एल. सेल, 03. मीड़ियम गंगा कब्जे के थैले से 01 नग टिफिन बम लगभग 02 कि.ग्रा, 03. सुण्डाम भीमा कब्जे के थैले से बारुद 100 ग्राम, 02 नग इंजेक्शन सीरिज, 05 नग पेंसिल सेल, 06. नुप्पो मंगा कब्जे के थैले से 10 नग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, इलेक्ट्रिक स्वीच, इलेक्ट्रिक वॉयर, 07. हेमला नंदा कब्जे के थैले से 10 नग जिलेटीन रॉड बमरामद किया गया। उपरोक्त सामाग्री को रखे जाने के संबंध में गहन पूछताछ करने पर बड़े नक्सलियों के कहने पर सुरक्षा बलों को नुकसान पहूंचाने की नीयत से रखना बताया गया।

भाजपा ने किया मतदाता अभिनंदन समारोह, मतदाताओं का माना आभार

जगदलपुर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के किलेपाल में विधानसभा स्तरीय मतदाता अभिनंदन समारोह आयोजन किया गया। जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को विजयी बनाने चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र की जनता व मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। मतदाता अभिनंदन समारोह में पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, भाजपा जिला अध्यक्ष रूपसिंह मण्डावी, चित्रकोट विधायक विनायक गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि देश की जनता व देश के करोड़ों मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में भाजपा व एनडीए पर भरोसा जताया, जिसकी बदौलत केन्द्र में पुनः एनडीए सरकार बनी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का नेतृत्व कर रहे हैं। भाजपा के लिये राष्ट्र का विकास व जनता की सेवा सदैव सर्वोपरि है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में जनता के आशीर्वाद से भाजपा को बड़ी विजय मिली है। चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र की समस्त सम्मानीय जनता व मतदाताओं का अभिनंदन करते हुये भारतीय जनता

पार्टी आभार व्यक्त करती है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता की सेवा व क्षेत्र के विकास के लिये सदैव सजगता से कार्य करेगा। साथ ही केन्द्र सहित प्रदेश की सभी जनकल्याण कारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने के काम निरंतरता से होते रहेंगे। अभिनंदन समारोह का संचालन संतोष ठाकुर ने किया।

इस दौरान पूर्व विधायक लच्छू राम कश्यप, बैदूराम कश्यप ,जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप,संतोष बघेल,महामंत्री रामाश्रय सिंह, वेद प्रकाश पांडेय,बाबुल नाग, फूल सिंह सेठिया,मण्डल अध्यक्ष नारायण ठाकुर,नवीन विश्वकर्मा,बोनजा राम, के. जानकी राव,संतोष बघेल, कामदेव बघेल ,नरसिंह ठाकुर,रैतु राम, टुल्लू राम, मगतु कश्यप,बबलू कश्यप, भरत कश्यप,डॉ बसंत कश्यप, देवी प्रसाद, रामबती बघेल,पदमा कश्यप,भानवती कश्यप,प्रिया मुचाकी, संग्राम सिंह राणा, रोहित त्रिवेदी,रितेश जोशी,बामन राम बट्टी,कमल ठाकुर,बंटी ठाकुर,नवल कुंजाम , मालती मंडावी सहित भाजपा कार्यकर्तृता उपस्थित थे।

गुरुकुल आवासीय छात्रावास में छात्र को मधुमक्खियों ने काटा

गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में आदिवासी विकास विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिसमें गुरुकुल आवासीय छात्रावास में गुरुवार की सुबह छात्रावास में रहने वाले 14 वर्षीय छात्र पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से आहत छात्र गुरुवार को पूरा दिन और रात दर्द से तड़पता रहा, जब छात्रावास का कोई भी कर्मचारी उसे इलाज के लिए नहीं ले कर गया तो शनिवार को दोपहर बाद छात्र खुद ही जिला अस्पताल पहुंचा जहां उसे डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। मामले पर आदिवासी विकास विभाग से अब तक कोई जिम्मेदार सामने नहीं आया है।

नए सत्र में स्कूल खुले अभी 15 दिन भी नहीं बीते हैं और आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रवासो के गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आना शुरू हो गया है जिला मुख्यालय में आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त के निवास के ठीक सामने स्थित गुरुकुल आवासी सामान्य छात्रावास में छात्रावास के अंदर एक 14 वर्षीय छात्र युवराज पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया मधुमक्खियों के हमले से दर्द से कराहता छात्र गुरुवार को पूरा दिन और पूरी रात दर्द से तड़पता रहा और छात्रावास में पड़ा रहा।

इस दौरान छात्रावास के किसी भी कर्मचारी ने उसे अस्पताल ले जाकर चिकित्सा तक देना उचित नहीं समझा, इसके बाद कल शुक्रवार को दोपहर बाद छात्र खुद ही जिला अस्पताल पहुंचा और उसका इलाज शुरू हुआ डॉक्टर ने उसे दवा देकर उसे बोतल चढ़ाई गई। जब छात्रा को कुछ राहत मिली तब देर रात उसे छात्रावास भेज दिया गया। जहां से छात्र अकेले ही छात्रावास वापस आ गया मामले की जानकारी मिलने के बाद जब हम छात्र का हाल-चाल लेने छात्रावास पहुंचे तो पीढ़ी छात्र ने अपनी व्यथा सुनाई। इस दौरान रात 9:30 छात्रावास में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था, यह उसे छात्रावास का हाल है जो आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त के निवास के ठीक सामने स्थित है इससे जिले के अन्य छात्रावासों के स्थिति का आंकलन किया जा सकता है।

भिलाई स्टील प्लांट में हादसा

दहकती हुई पटरी स्टैंपिंग मशीन से उछलकर आई बाहर

भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट में रेल मिल में बड़ा हादसा हुआ है। यहां रेल पटरी प्रोडक्शन यूनिट में धधकती हुई पटरी स्टैंपिंग मशीन से उछलकर बाहर निकल गई। इसके बाद जमीन से 15 फीट ऊंचाई पर पटरी फंस गई।इस हादसे में अच्छी बात ये थी कि जिस केबिन में बैठकर वर्कर मशीन को ऑपरेट कर रहे थे,वहां पर पटरी नहीं गई।वरना एक बड़ी अनहोनी हो जाती।

बताया जा रहा है कि स्टैंपिंग टेबल से दहकती हुई रेल पटरी उछलते हुए केबिन की छत पर टिक गई। रोलिंग टेबल से बाहर निकलने की वजह से स्टैंपिंग मशीन के मोटर को भी नुकसान पहुंचा है। हाइड्रोलिंक सिस्टम को चलाने वाला सिस्टम भी इस हादसे के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है। हादसे में हाइड्रोलिक हॉज पाइप जल गई है।फिलहाल रोलिंग मशीन को हादसे के बाद बंद कर दिया गया है। हादसे के बाद से कर्मचारियों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई।इसके बाद फायर

ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई।

फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर तुरंत पहुंची और दहकती हुई पटरी के कारण आसपास लगी हुई आग पर काबू पाया।फायर ब्रिगेड की टीम सबसे पहले दहकती हुई पटरी को ठंडा कर रही है।इसके बाद उसे कटर से काटकर अलग-अलग टुकड़ों में काटा जाएगा।फिर पटरी को क्रेन की मदद से केबिन से हटाया जाएगा। इसके बाद ही स्टैंपिंग मशीन पर दोबारा काम शुरू होगा।

आपको बता दें कि इससे पहले भी यूनिवर्सल रेल मिल-यूआरएम में इस तरह की घटना हो चुकी है। जहां टेबल से हटने की वजह से टेस्टिंग रूम तक रेल पटरी घुस चुकी है। उस वक्त भी कर्मचारी बाल-बाल बचे थे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कोल वाशरी के कब्जे को लेकर कारोबारियों में विवाद

रायगढ़। ओडिशा के सुंदरगढ़ में कोल वाशरी में कब्जे को लेकर दो कोयला व्यवसायी आमने समाने आ गए। मामला सुंदरगढ़ जिले के हेमगिर कोल माइंस का है। जहां कब्जे को लेकर दो कारोबारी गुटों के बीच जमकर मारपीट, आगजनी, तोड़फोड़ के साथ कई राउंड फायरिंग हुई। विवाद में रायगढ़ के दो कोल कारोबारियों के नाम सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक लंबे अर्से से रायगढ़ के दोनों कोल कारोबारियों के बीच ओडिशा के सुन्दरगढ़ जिले में आने वाले गर्जना बहाल में स्थित कोलवाशरी के मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद के बाद रायगढ़ के ही एक गुट ने कोलवाशरी में कब्जा जमाकर ताला बंद कर दिया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद शुक्रवार को रायगढ़ के ही दूसरे गुट के लोग हथियारों से लैस होकर ओडिशा स्थित कोलवाशरी पहुंचे। जिस समय दूसरा गुट पहुंचा उस समय पहला गुटा ओडिशा के गुर्गों के सहारे पहले से ही वाशरी पर कब्जा जमा रखा था। आमने-सामने होने के बाद दोनों ही गुटों में गोलियां चलने लगी।

एसीबी ने रिश्वत लेते नायब तहसीलदार को पकड़ा

धमतरी। धमतरी में कब्जा जमीन मामले में

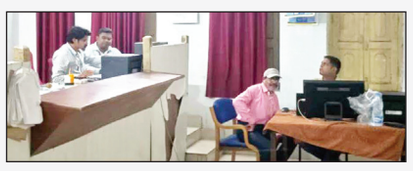

एक ग्रामीण से 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते एसीबी ने नायब तहसीलदार को पकड़ा है। धमतरी तहसील कार्यालय में पदस्थ नायब तहसीलदार खीरसागर बघेल को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। टीम के अधिकारी कर्मचारी आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रार्थी दिलीप पुरी गोस्वामी ने जमीन कब्जा मामले को लेकर रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी कार्यालय में किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीबी की टीम ने पांच जुलाई को विशेष रणनीति के तहत धमतरी पहुंचकर कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि संबंधित जमीन 85 डिसमिल है। जिस पर कब्जा को लेकर विवाद चल रहा था।

अवैध रूप से संचालित आठ क्लीनिकों पर जड़ा ताला

जगदलपुर। बस्तर में जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा झोलाछाप डॉक्टरों एवं बिना पंजीयन क्लीनिक चलाने वालों के खिलाफ जांच एवं कार्रवाई का अभियान जारी है। आकस्मिक जांच के दौरान अवैध रूप से संचालित 8 क्लीनिकों को जिला प्रशासन की टीम ने सील कर दिया है। बिना पंजीयन क्लीनिक का संचालन करने वाले 10 क्लीनिक संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई बस्तर जिले में झोलाछाप डॉक्टरों अवैधानिक तरीके से क्लीनिक का संचालन तथा गांव-गांव घूमकर मरीजों का इलाज करने के संबंध में मिल रही शिकायतों को देखते हुए की जा रही है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम जिला मुख्यालय से लेकर विकासखण्ड मुख्यालयों एवं गांवों में संचालित दवाखानों, डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर्स में लगातार दबिश देकर उनकी वैधानिकता की जांच-पड़ताल कर रही है। नर्सिंग होम एक्ट जगदलपुर के नोडल अधिकारी डॉ. टीएस नाग जांच-पड़ताल के लिए औचक रूप से पहुंची।

घर के कमरे में खेल रहे थे जुआ, पुलिस ने की छापेमारी

दुर्ग। दुर्ग जिले के खुर्सीपार थाना और एसीसीयू टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मकान के ऊपर मंजिल पर जुआ खेलते 10 आरोपी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 58,820 रूपये बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि सभी जुआरी भिलाई के रहने वाले हैं। जो घर के कमरा में जुआ खेल रहे थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि खुर्सीपार थाना क्षेत्र के श्रीराम मेडिकल दुकान के ऊपर कमरे में जुआ खेल रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। पकड़े गए आरोपियों में सुमित सिंह, सूरज महतो, अनिल अडियाल, आनंद राव, पंकज दास, शेखर सिंह, जी गौतम, शेख सानु, विशाल कुमार, बोल बम महतो का नाम शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 52 ताश पत्ती समेत 58 हजार 820 रूपये नगदी रकम बरामद की है।

पैसे डबल करने झांसा देकर लोगों से लाखों रुपये ऐंठे

बिलासपुर। बिलासपुर में पैसे डबल करने का झांसा देकर एक महिला ने लोगों से लाखों रुपये ऐंठ लिये। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला ने शेयर मार्केट में रुपये लगाने का झांसा लोगों को दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुरा मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है। पचपेड़ी धूर्वाकारी में रहने वाली राधिका ने 15 से 20 लोगों के समूह को निशाना बनाया, इसमें महिला-पुरुष शामिल हैं। उसने उनसे शेयर मार्केट में रुपये लगाकर पैसे डबल करने का झांसा दिया। राधिका ने उन लोगों को बताया कि शेयर मार्केट में रुपये लगाओ, जो एक साल में दोगुनी रकम मिलेगी। राधिका की बातों में आकर गांव के लोगों ने पैसे लगा दिये। करीब 84 लाख रुपए किस्तों मे नगद व ऑनलाइन उस दे दिए। एक साल निकल जाने के बाद महिलाओं को रकम वापस नहीं मिली। तो उन्होंने राधिका से इसके बार में पूछा तो वह टालमटोल करने लगी और कुछ नहीं का इंतजार करने की बात कही।

30 हीरों के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार, हीरा बेचने की फिराक में घूम रहे थे आरोपी

गरियाबंद। गरियाबंद में तीन संदिग्ध व्यक्ति दो अलग-अलग मोटरसाइकिल में अपने पास बहुमूल्य हीरा रखकर ग्राम पटपरपाली से चरौदा की ओर निकले थे। मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से परिवहन की जानकारी मिलने पर स्टाफ के साथ घटना स्थल रवाना हुआ। जो ग्राम कंदागड़ी मोड़ पहुंच कर नाकाबंदी किया गया, कुछ देर के बाद मोटर साइकिल टीवीएस एवं मोटर साइकिल डीलक्स दो अलग- अलग मोटर साइकिल में तीन व्यक्ति आ रहे थे जिन्हे पुलिस द्वारा रोककर पूछताछ करते हुए तीनों संदेही आरोपी का तलाशी लेने पर संदेही चंद्रशेखर ठाकुर के कब्जे से 30 नग छोटे-बड़े चमकीले बहुमूल्य खनिज पदार्थ हीरा मिला। जिसे समक्ष गवाहन की उपस्थित में कब्जा पुलिस लिया गया।

आरोपियों का कृत्य अपराध धारा सदर 21(4) माइनिंग एक्ट का पाए जाने से थाना छुरा में आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी छुरा उप निरीक्षक दिलीप मेश्राम, जयप्रकाश मिश्रा,गिरधारी लाल ध्रुव, कृष्ण यादव, लैनदास रत्नाकर, अखिलेश वैष्णव राजकुमार मरकाम के साथ साइबर टीम से.स्ट्र मनीष वर्मा, अंगद राव,सतीश गिरी, देवेंद्र सोनवानी, गंगाधर सिन्हा, कृतेश प्रजापति का भूमिका सराहनी रहा।

बारिश के कारण सब स्टेशन और खेत राख से पटा

पर्यावरण विभाग ने कृषि उपज मंडी के सचिव को जारी किया नोटिस

कोरबा। कोरबा के भालुसटका गांव के पास मौजूद विद्युत सब स्टेशन के साथ ही करीब दस किसानों के खेतों में राख का प्रवाह होने के मामले को पर्यावरण व संरक्षण विभाग ने काफी गंभीरता से लिया है। विभाग ने कृषि उपज मंडी के सचिव को राख का उठाव जल्द से जल्द करने हेतु नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही मामले की जांच शुरु कर दी है।

पिछले 6 दिनों की बारिश में जिस तरह से भालू सटका गांव के पास मौजूद सब स्टेशन और करीब दस किसानों के खेतों में राख का प्रवाह हुआ है,उसे क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल ने काफी गंभीरता से लिया है। मामला सामने आने के बाद विभागीय अधिकारी खुद मौके पर पहुंचे और स्थित का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने कृषि उपज मंडी के सचिव को नोटिस जारी कर राख का उठाव जल्द से जल्द करने की बात कही है।

भालूसटका स्थित सब स्टेशन कई एकड़ जमीन पर बनाया गया है जहां निर्माण के समय संबंधित विभाग के द्वारा पूरे एरिया को राखड़ से पाठ दिया गया उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी फीलिंग कर दिया गया खामियाजा लगातार बारिश होने के बाद सामने आया जहां कहीं जगह पर बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई है वही राख बहकर सब स्टेशन के अंदर तक घुस गया यही नहीं आसपास लगभग 10 किसानों के खेत भी राखड़ से पट गया। किसानों ने इसकी शिकायत कलेक्टर और संबंधित विभाग से

किया इसके बाद पर्यावरण विभाग में मामले को गंभीरता से लेते हुए आधिकारिक खुद घटना स्थल पर पहुंचे और जायजा लिया।

राखड़ की परत इतनी ज्यादा थी कि पिछले दो दिनों से मशीन के सहारे बाहर निकाला जा रहा है और ट्रैक्टर में लोड कर उसे बाहर फेंका जा रहा है। किसानो की माने तो खेत मे राखड़ पट जाने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा ऐसे में वो खेती कैसे करेंगे उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है उन्हें शासन जांच कर उचित मुआवजा प्रदान करे।

पर्यावरण अधिकारी प्रेमेंद्र पाण्डेय ने कहा,कि मामले को जांच में ले लिया गया है। जांच के दौरान राख पाटने के नियम और शर्तों पर गहनता से विचार किया जाएगा। बरसात के पानी के साथ भारी मात्रा में राख का प्रवाह खेतों और सब स्टेशन में हुआ है,जहां से राख को हटाने का काम जारी है। मामले की जांच शुरु हो गई है,देखने वाली बात होगी,कि जांच के दौरान कौन कौन से तथ्य सामने आते है।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल हरिचंदन और मुख्यमंत्री साय का बिलासपुर हेलीपैड पर स्वागत

बिलासपुर। राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन

और मुख्यमंत्री साय का बिलासपुर पहुंचने पर हेलीपैड पर आत्मीय स्वागत किया गया। हरिचंदन और मुख्यमंत्री यहां पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन विश्व विद्यालय के छठें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। हेलीपैड पर प्रमुख रूप से केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कुलपति वंशगोपाल सिंह, कुलपति श्री एबीएन बाजपेई सहित विधायक श्री अमर अग्रवाल, विधायक श्री धरमलाल कौशिक, विधायक श्री धरमजीत सिंह, विधायक श्री सुशांत शुक्ला और आईजी श्री संजीव शुक्ला ,कलेक्टर श्री अवनीश शरण, एसपी श्री रजनेश सिंह ने स्वागत किया।

कांग्रेस नेताओं ने फिर छोड़ी पार्टी

बिलाईगढ़। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले से कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोडऩे की खबर आ रही है। जिले में एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नगर पंचायत भटगांव अध्यक्ष सहित कांग्रेस समर्थित सभी पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा पूर्व एल्डरमेनों ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। सभी ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को व्हाट्सएप के माध्यम से अपना इस्तीफा पत्र भेजा है। मिली जानकारी के अनुसार अध्यक्ष सहित सभी पार्षदों ने भ्रष्टाचार का आरोप के चलते इस्तीफा दिया है। दरअसल, भटगांव नगर पंचायत में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। विधायक कविता प्राण लहरे के साथ कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया था। अब ऐसे में भटगांव नगर के जनप्रतिनिधियों का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

रायपुर में रिश्वत लेते महिला टीआई गिरफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में महिला टीआई को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। महिला टीआई ने दहेज प्रताड़ना के मामले में एफआईआर लिखने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। टीआई ने पैसे नहीं देने पर एफआईआर लिखने से इंकार कर दिया। इस पर प्रार्थी ने 20 हजार रुपये महिला टीआई को दी। बताया जा रहा है कि उसने एफआईआर दर्ज करने के नाम पर 50 हजार की मांग की थी। एसीबी की टीम ने महिला टीआई को गिरफ्तार किया है। रायपुर महिला थाने की टीआई वेदवती दरियो को एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह घटना तब हुई, जब महिला टीआई ने दहेज प्रताड़ना के मामले में एफआईआर लिखने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। मामले में प्रार्थी ने 20 हजार रुपए टीआई को दे दी, लेकिन प्रार्थी प्रीति बंजारे से पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के मामले में अपराध दर्ज करने के नाम पर 50 हजार रुपये की मांग की थी। महिला और टीआई के साथ समझौता कर एफआईआर लिखने के लिए 35 हजार रुपये में सौदा पका हुआ। बता दें कि महिला टीआई बिना पैसों के अपराध दर्ज करने से मना कर दी थी। इतना ही नहीं उसने शाम को पैसों के साथ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बुलाई। प्रार्थी पैसों के साथ एफआईआर कराने पहुंची। इस दौरान एसीबी की टीम ने टीआई वेदवती दरियो को रंगे हाथों नगदी रकम के साथ पकड़ा। मामले में एसीबी की टीम की ओर से कार्रवाई जारी।

राजनीतिक वजूद झुलसने के डर से बेचैन भूपेश कर रहे झूठा प्रलाप : मूणत

■ पूर्व मंत्री मूणत ने पूर्व सीएम बघेल पर साधा निशाना

रायपुर। पूर्व मंत्री और विधायक राजेश मूणत ने शराब घोटाले से जुड़े नकली होलोग्राम की जब्ती के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बघेल की ज्ञानेंद्रिय अब जाकर हरकत में आई है, जब एसीबी और ईओडब्ल्यू ने धनेली गाँव में छापा मारकर शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर के खेत की खुदाई करके वहाँ से सैकड़ों अधजले नकली होलोग्राम का जखीरा जब्त किया। विधायक मूणत ने कहा कि घोटाले के गिरफ्तार आरोपियों द्वारा पूछताछ के दौरान नकली होलोग्राम का सच स्वीकार करने के बाद भी भूपेश बघेल इस मामले में फिर मिथ्या प्रलाप करके रोज नया प्रपंच फैलाते हुए जरा भी शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मूणत ने कहा कि शराब घोटाले के मामले में बघेल द्वारा रचे जा रहे राजनीतिक प्रपंच की उम्र ज्यादा लंबी नहीं है। देर-सबेर इस मामले का पूरा सच सामने आएगा और फिर दोषी चाहे कोई भी हो, उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे

होगी। बघेल यह बात अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जाँच की आँच में देर-सबेर उनका राजनीतिक वजूद झुलसने वाला है, यही डर बघेल को बेचैन कर रहा है, उनसे मिथ्या प्रलाप करा रहा है। मूणत ने सवाल किया कि आखिर नकली होलोग्राम मामले में बघेल की जुबान तब क्यों चली, जब ढेबर के खेत से नकली होलोग्राम का जखीरा पकड़ाया और साक्ष्य मिटाने के आरोप में तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई? बघेल होलोग्राम बनाने वाली फैक्ट्री को फर्स्ट बेनिफिशियरी बताकर आखिर अपने धत्कर्म पर कब तक पर्दा डालने की नाकाम कोशिश करते रहेंगे? फैक्ट्री मालिक गुजरात का होना इस पूरे मामले उतना मायने नहीं रखता, जितना यह मायने रखता है कि उस कम्पनी को प्रक्रिया का उल्लंघन करके होलोग्राम बनाने का टेंडर किसके शासनकाल में देकर नकली होलोग्राम बनवाए गए और फिर उसे छत्तीसगढ़ में शराब के गोरखधंधे में इस्तेमाल किया गया? बघेल को अब यह कैसे पता चला कि फैक्ट्री मालिक गुजरात का है? क्या बघेल बाकी का प्रलाप छोड़कर प्रदेश को इन सवालों का जवाब देने का माद्दा रखते हैं?

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मूणत ने कहा कि शराब घोटाले को लेकर हो रही जाँच पर भूपेश बघेल कहते थे कि इसमें तानाशाही हो रही है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। शराब घोटाले के जो आरोपी है और जो गिरफ्तार हुए हैं, अब तो उन्होंने भी साफ कर दिया है कि हम नकली होलोग्राम बनाते थे। कांग्रेस की पिछली भूपेश सरकार के कार्यकाल में हुए शराब घोटाले को लेकर लगातार हो रहे ताजा खुलासों और बरामदगी के मद्देनजर कांग्रेस के भ्रष्ट कारनामों को लेकर तीखा हमला बोलते हुए मूणत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने शराब के गोरखधंधे को बढ़ावा देकर जितनी काली करतूतें की हैं, वह अब सामने आ रही हैं, इसलिए बघेल रोज बिफर रहे हैं। भूपेश सरकार न केवल शराब की कोचियागिरी कर रही थी, बल्कि नकली और अवैध शराब के जरिए एक तरफ जान-माल के साथ घिनौना खिलवाड़ तक कर रही थी तो दूसरी तरफ प्रदेश के सरकारी खजाने पर डाका डाल रही थी। अब यह बात अब आईने की तरह साफ हो गई है कि प्रदेश का शराब घोटाला पिछली कांग्रेस सरकार की छत्रछाया में ही फल-फूल रहा था। जाँच के दौरान इस मामले की कलई खुलने से सशंकित तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता अनर्गल प्रलाप कर जाँच एजेंसियों को केंद्र सरकार की एजेंट बताकर भ्रम फैलाते रहे, पर अब सच का सामना करने के लिए बघेल को तैयार हो जाना चाहिए।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मूणत ने कहा कि ताजा खुलासे और बरामदगी तो अभी इस पूरे घोटाले का ट्रेलर भर है, पूरी पिक्चर तो पर्दे पर अब आएगी। नित-नए चौंकाने वाले खुलासों की ऐसी खबरें तो अब लगातार आएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल, जो भ्रष्टाचार के तमाम खुलासों के मौकों पर भ्रष्टाचार के आरोपियों के वकील बनकर खड़े होते रहे हैं, शराब घोटाले को लेकर लगातार झूठ बोलकर प्रदेश को गुमराह करते रहे। इस पूरे मामले में बघेल की भूमिका को भी जाँच के दायरे में लाने की मांग करते हुए मूणत ने सवाल दागा कि शराब घोटाले के लिए ढेबर परिवार को संरक्षण देने के एवज में वह कितनी कीमत वसूल रहे थे? प्रदेश सरकार की जानकारी में इतना बड़ा घोटाला फल-फूल रहा था और बघेल इस मामले को लेकर अनभिज्ञता का पाखंड रचते रहे। न केवल शराब, बल्कि कोयला और महादेव एप समेत अन्य तमाम घोटाले में किंगपिन किसे कहा गया है, पॉलिटिकल मास्टर कौन है, यह अब किसी से छिपा नहीं है। मूणत ने कहा कि इससे पहले कोयला घोटाले में भी बघेल की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं और उस पूरे घोटाले के 'पोलिटिकल मास्टर' के तौर पर बघेल का नाम हर जुबान पर है, तो अब बघेल प्रदेश को यह बताएँ कि क्या कोयला घोटाला की तरह ही शराब घोटाला के भी 'पोलिटिकल मास्टर' वह खुद ही थे?

कोटा पुलिस के नोटिस पर कुणाल शुक्ला का जवाब

आरटीआई एक्टिविस्ट ने कहा- डरने वाला नहीं, स्पीकर ओम बिरला डीप फेक केस

रायपुर। राजधानी रायपुर के टैगोर नगर में रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला के घर शुक्रवार को राजस्थान की कोटा पुलिस पहुंची। कोटा पुलिस ने कुणाल शुक्ला को एक नोटिस दिया और 7 दिन के अंदर आरटीआई कार्यकर्ता को कोटा के किशोरपुरा थाने में उपस्थित होने के लिए कहा।

13 अप्रैल को कोटा शहर के भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने वहां के किशोरपुरा थाने में लिखित रिपोर्ट कराई। इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे ओम बिरला के खिलाफ सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो वायरल किया जा रहा है। वीडियो में ओम बिरला की आवाज हूबहू मिल रही है। नौशाद और आशव के फेसबुक पेज पर व्हाट्सएप ग्रुप में मनगढ़ंत झूठा और प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला वीडियो अपलोड किया गया है। इसे आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला ने भी शेयर किया था।

कोटा शहर के भाजपा जिला अध्यक्ष ने शिकायत में आगे बताया कि फर्जी वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना आपराधिक कृत्य हैं। ओम बिरला भाजपा प्रत्याशी के साथ-साथ

लोकसभा अध्यक्ष हैं। अब संवैधानिक पद पर बैठे शख्स के खिलाफ डीप और फेक वीडियो बनाकर ओम बिरला की छवि को धूमिल किया जा रहा है।

कोटा पुलिस के नोटिस पर कुणाल शुक्ला ने कहा- कोटा पुलिस ने प्री अरेस्ट नोटिस दिया है। लेकिन मैं कहता हूं कि सात दिन बाद क्यों वह आज ही मुझे गिरफ्तार कर लें। मैं हमेशा किसानों, गरीबों, मजदूरों के लिए आवाज उठाता रहा हूं। नरेंद्र मोदी की तानाशाही अगर ये समझती है कि मेरी आवाज दबा लेगी तो उनको बताना चाहूंगा कि मेरी आवाज वह नहीं दबा पाएंगे। मैं पुलिस से या तानाशाही से डरना वाली नहीं हूं। मैं और भी मुखरता से अपनी आवाज उठाउंगा।

इस मामले में राजस्थान पुलिस आरोपी नौशाद और आशव शर्मा को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके बाद अब इसी केस में कुणाल शुक्ला पर कार्रवाई की जा रही है। केस में आईटी एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला को भूपेश सरकार के कार्यकाल के दौरान कबीर विकास संचार केंद्र शोधपीठ का अध्यक्ष बनाया गया था। शोध पीठ की स्थापना कुशाभाव ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के अंतर्गत की गई थी।

संघ लोक सेवा आयोग की ईपीएफओ और ईएसआईसी के अधिकारियों के लिए परीक्षा आज

रायपुर। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 7 जुलाई को ईपीएफओ में एसिटेंस ऑफिसर तथा ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर के लिए परीक्षा आयोजित की गई है। इसी परिपेक्ष्य में कलेक्ट्रेट स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में परिवहन अधिकारी सह पर्यवेक्षक तथा केंद्राध्यक्ष का प्रशिक्षण हुआ। जिसमें कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह व आब्र्जवर श्री श्रवण बंसल शामिल हुए। कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि पूरी परीक्षा व्यवस्था के दौरान गंभीरता बरती जाए। कलेक्टर ने अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि परीक्षा शुरू होने से आधा घंटे पहले केंद्र में पहुंच जाए। निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश नहीं दी जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग के नियमों का पालन किया जाए और सभी अभ्यर्थियों से विनम्र व्यवहार रखें। कलेक्टर ने कहा कि परीक्षा केंद्रों में लाइट, पंखा,पार्किंग, टेबल व पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

आब्र्जवर श्री श्रवण बंसल ने कहा कि परीक्षा केंद्रों में पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर ही प्रवेश दी जाए। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारी के साथ केंद्रों में परीक्षा कराई जाए। परीक्षा केंद्रों में सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप, संघ लोक सेवा आयोग के श्री राजकुमार सोलंकी, एडीएम श्री कीर्तिमान सिंह राठौर, रोजगार अधिकारी श्री केदार पटेल व अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि परीक्षा प्रथम पाली में 9.30 बजे से 11.30 बजे तक 3 केंद्रों में और द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4 बजे के मध्य 20 केंद्रों में आयोजित की जाएगी।

सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने से होगी प्रदेश और देश की समृद्धि: कश्यप

रायपुर। सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि सहकारी समितियों के सशक्तिकरण से किसानों सहित गांव, प्रदेश और देश की समृद्धि जुड़ी हुई है। सबकी सहभागिता से सबका विकास ही सहकारिता का मूल उद्देश्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के गांव, गरीब और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सहकार से समृद्धि को साकार करने का आव्हान किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली हमारी सरकार का ध्येय वाक्य भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है और इसी ध्येय वाक्य को लेकर हमारी सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। उन्होंने सहकारी समिति से जुड़े लोगों से कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में हमारा काम जमीनी स्तर पर दिखनी चाहिए। सबकी सहभागिता और सहयोग से ही हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकेंगे।

मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि धरती मां को हम वसुंधरा के नाम से भी जानते हैं। इस वसुंधरा की हम पूजा करने वाले लोग है। जहां भी हल चलाकर हम बीज बो देते हैं। वसुंधरा हमें जीवकोपार्जन के लिए कई गुना अनाज देती है। उन्होंने कहा कि सहकारी समिति केवल धान, बीज खरीदी और बिक्री का केन्द्र नहीं, बल्कि इसे मल्टी एक्टिविटिज तथा कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार ने प्रदेश के किसानों से एक-एक दाना धान खरीदने का वादा किया था। हमारी सरकार ने इन वादों के मुताबिक 3100 प्रति क्विंटल के मान से राज्य के लगभग 25 लाख किसानों से 145 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि किसानों की प्रगति हमारी प्राथमिकता में है। किसानों के प्रारंभिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक साढ़े 5 हजार करोड़ रूपए ऋण वितरण किए जा चुके हैं।

सेन्ट्रल हॉल में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधान सभा परिसर स्थित सेन्ट्रल हॉल में प्रतिष्ठापित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैल

चित्र पर शनिवार को उनकी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिव दिनेश शर्मा ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किये। इस अवसर पर विधान सभा परिसर स्थित प्रेक्षागृह के मुख्य द्वार पर स्थापित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बस्ट आकार की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की गयी। इस अवसर पर विधान सभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित कर उनका स्मरण किया।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, राजनांदगांव (छ.ग)

संक्षिप्त मैनुवल निविदा सूचना क्रमांक-5

क्रमांक / 1644/वलेलि / ग्रायांसेवा/2024-25 राजनांदगांव, दिनांक 04.07.2024

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से पंजीकृत एकीकृत पंजीयन प्रणाली से प्रपत्र 'ए' में दर्शित निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु दर प्राप्त करने आनलाईन मैनुवल निविदा आमंत्रित की जाती है:-

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू. लाख में)	निविदा आमंत्रण	निविदा कार्यालय में पहुंचने कि अंतिम तिथि
पोस्ट मार्टम भवन निर्माण ग्राम औंधी वि.ख. मानपुर , Distt.- Mohala-Manpur-A.chowki(C.G.)	14.32	द्वितीय बार	15.07.2024
पोस्ट मार्टम भवन निर्माण ग्राम मोहला वि.ख. मानपुर, Distt.- Mohala-Manpur-A.chowki(C.G.)	14.32	द्वितीय बार	15.07.2024
नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य ग्राम मासूल ग्रा.पं. घोटिया वि.ख. मानपुर Distt.- Mohala-Manpur-A.chowki(C.G.)	11.89	द्वितीय बार	15.07.2024
विकास खण्ड क्षेत्रीय जोनल निविदा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग खैरागढ़ अंतर्गत विभिन्न मदों में स्वीकृत 10.00 लाख से कम लागत के भवन एवं अन्य प्रकार के निर्माण कार्य	40.00	द्वितीय बार	15.07.2024
विकास खण्ड क्षेत्रीय जोनल निविदा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग छुईखदान अंतर्गत विभिन्न मदों में स्वीकृत 10.00 लाख से कम लागत के भवन एवं अन्य प्रकार के निर्माण कार्य	40.00	द्वितीय बार	15.07.2024
हाईटेक नर्सरी में भंडार गृह निर्माण कार्य बीरूटोला विकास खण्ड छुईखदान जिला खैरागढ़ छुईखदान-गंडई (छ.ग.)	5.66	चतुर्थ बार	12.07.2024

उपरोक्त कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेबपोर्टल http://eproc.cgstate.gov.in में दिनांक 06.07.2024 से देखी जा सकती है। निविदा कार्यालय में पहुंचने की अंतिम तिथि उपरोक्तानुसार सायं 5.30 तक है।

कार्यपालन अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग-राजनांदगांव

जी-242500889/7

10-10 सांसद के बाद भी छत्तीसगढ़ की केंद्र में कोई सुनवाई नहीं : भूपेश बघेल

रायपुर। एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सहित केंद्र की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

ने लगातार रद्द हो रही ट्रेन, प्रधानमंत्री आवास, शराब घोटाला, महादेव सट्टा सहित कई मुद्दों पर भाजपा पर तंज कसा।

लगातार छत्तीसगढ़ में रद्द हो रहे ट्रेनों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा यात्री ट्रेनों की हालत बहुत खराब है। छत्तीसगढ़ में 212 ट्रेनों के 1000 से ज्यादा फेरे रद्द कर दिए गए हैं। माल लदान का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। कोरोना काल से अब तक केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ के यात्रियों के साथ दोयम दर्जे की व्यवहार कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार समेत केंद्र की सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ ने 10-10 सांसद जितवाकर भेजे हैं। भूपेश बघेल ने कहा- छत्तीसगढ़ में स्कूल खुल गए हैं। लेकिन अब तक स्कूलों में रेडी टू ईट अब तक शुरू नहीं हो पाया है। रेडी टू ईट का पिछले बार का भुगतान अब तक नहीं हुआ जिससे बच्चों को रेड टू ईट नहीं मिल रहा है। विधानसभा में सेल्फ हेल्फ ग्रुप को देने की बात हुई थी लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई।

आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला को भेजे गए नोटिस पर भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा लोकसभा में जो कार्रवाई हो रही है वह पूरी दुनिया देख रही है। कई टिप्पणियां लोकसभा सदस्यों ने भी किया, पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर टिप्पणियां की गई है, जो गलत है उसे गलत कहा है, यह तानाशाही रवैया है। बदले की कार्रवाई और डराने धमकाने के कारण जनता ने 303 से घटाकर 240 सीटों पर ला दिया है। इसे ही कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया।

बघेल ने कहा- महादेव सट्टा एप में अब तक एफआईआर नहीं हुई हैं। हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, मुंबई, ओडिशा, यूपी से गिरफ्तारी हो रही है। इसका मतलब भाजपा शासित राज्यों में महादेव सट्टा चल रहा है। यदि दूसरे राज्यों में नहीं हो रहा है इसका मतलब कांग्रेस ने एफआईआर करवाएं हैं। इस वजह से केस को बंद भी नहीं कर रहे हैं। महादेव एप के आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। शराब घोटाले पर हो रही ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा मुझे जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है, ईडी ने 2200 करोड़ रुपए का आरोप लगाया है। होलोग्राम फैक्ट्री मालिक के यहां लगता है, इस हिसाब से फर्स्ट बेनिफिशियरी फैक्ट्री मालिक होगा, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ईओडब्ल्यू में आपकी बाध्यता है, जहां से घटना घटी है उसके खिलाफ पहले कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे वसूली कब होगी उन पर कारवाई कब होगी, यह केवल आई वॉश है।

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग
कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र. 1, रायपुर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

निविदा सूचना क्र. 03/व.ले.लि./2024-25 रायपुर, दिनांक- 4/7/2024

मैन्युअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र. 01, रायपुर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग के दिनांक 01/08/2010 से प्रचलित एस.ओ.आर. तथा दिनांक 22.08.2022 तक जारी संशोधन दर पर निम्नलिखित निविदा आमंत्रित किया जाता हैं। विवरण निम्नानुसार है-

स. क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	अमानत राशि रू. में
1	2	3	4
	अभनपुर नहर उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत एप्रोच चैनल एवं पम्प हाऊस में जमा मिट्टी निकालने का कार्य	19.38 लाख	रु. 14600/-

निविदा प्रपत्र का मूल्य	रू. 750/-
कार्य पूर्णता का समयावधि	2 माह वर्षा ऋतु सहित
निविदा प्राप्ति हेतु सक्षम श्रेणी	द श्रेणी एवं ऊपर
निविदा क्रय की अंतिम तिथि	दिनांक 12.07.2024 समय 5.30 शाम तक
निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	दिनांक 19.07.2024 समय 5.30 शाम तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 22.07.2024 समय 11.30 से

निविदा के अन्य शर्तें कार्यालयीन अवधि में कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र. 01. रायपुर के कार्यालय में दिनांक 12.07.2024 तक देखा जा सकता हैं।

कार्यपालन अभियंता
जल प्रबंध संभाग क्र. 1 रायपुर (छ.ग.)

जी- 242500884/5

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, धमतरी (छग)

संशोधित निविदा आमंत्रण सूचना

इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित निविदा सूचना क्र.-01 दिनांक-15.06.2024 जी.क्र.-242500398 को अपरिहार्य कारण से निविदा के समय सारणी एवं निविदा में आंशिक संशोधन किया जाता है-

समय सारिणी-

क्र.	विवरण	पूर्व तिथि	संशोधित तिथि
01	खण्ड कार्यालय में निविदा प्रपत्र क्रय करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	दिनांक 04.07.2024 शाम 5.30 बजे तक	दिनांक 19.07.2024 शाम 5.30 बजे तक
02	खण्ड कार्यालय से कोरे निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	दिनांक 08.07.2024 शाम 5.30 बजे तक	दिनांक 22.07.2024 शाम 5.30 बजे तक
03	खण्ड कार्यालय में निविदायें केवल रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट डाक से प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 12.07.2024 अपरान्ह 3.30 बजे तक	दिनांक 26.07.2024 अपरान्ह 3.30 बजे तक
04	निविदायें कार्यपालन अभियंता, कार्यालय धमतरी में खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 12.07.2024 अपरान्ह 4.30 बजे से	दिनांक 26.07.2024 अपरान्ह 4.30 बजे से

निविदा की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, धमतरी (छग)

जी- 242500887/4

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर

(केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ) ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना

Main Portal: https: // eproc.cgstate.gov.in

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है:-

स. क्र.	सिस्टम निविदा क्रमांक/दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रूपये लाख में)
1	155631 द्वितीय आमंत्रण 01.07.2024	कंतेली सूरजपुरा डिंडौरी कोयलारी मार्ग लंबाई 6.97 कि.मी. का निर्माण कार्य।	614.94
2	155633 प्रथम आमंत्रण 01.07.2024	जिला राजनांदगांव के औंधी में शासकीय नवीन महाविद्यालय भवन का वाटर सप्लाई,सेनेटरी फिटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं विद्युतीकरण सहित शेष निर्माण का कार्य।	316.63
3	155645 प्रथम आमंत्रण 02.07.2024	जिला कबीरधाम में ब्लॉक पंडरिया के कुई कुकदूर में शासकीय नवीन महाविद्यालय भवन का वाटर सप्लाई, सेनेटरी फिटिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य। (जमा कार्य)।	461.32
4	155648 प्रथम आमंत्रण 02.07.2024	जिला बलौदाबाजार के कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलाईगढ़ नवीन भवन एवं तहसील कार्यालय नवीन भवन बिलाईगढ़ का निर्माण कार्य, वॉटर सप्लाई, सेनेटरी फिटिंग एवं विद्युतीकरण कार्य सहित। (जमा मद का कार्य) बलौदाबाजार संभाग बलौदाबाजार ।	374.46
5	155662 प्रथम आमंत्रण 02.07.2024	जिला रायपुर के विधानसभा मोड़ जंक्शन से मंदिर हसौद जंक्शन तक रिंग रोड क्रमांक तीन में मेटल क्रश बेरियर एवं काऊ केचर स्ट्रीट लाईट लंबाई 7.50 कि.मी. का निर्माण कार्य। (संभाग क्र. 3 नवा रायपुर)।	698.00
6	155663 प्रथम आमंत्रण 02.07.2024	जिला बलरामपुर रामानुजगंज बसंतपुर से रामनगर मार्ग (मुख्य जिला मार्ग क्र. 278) के कि.मी. 1 से 6/6 = 5.60 कि.मी. एवं कि. मी. 9/6 से 15/2 = 11.40 कि.मी. में मजबूतीकरण निर्माण कार्य।	1289.20

निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि सं.क्र. 01 दिनांक 12.07.2024, सं.क्र. 02 दिनांक 22.07.2024 निर्धारित है। एवं अन्य शेष निविदाओं के लिए दिनांक 24.07.2024 निर्धारित है। निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाईट में देखे जा सकते है।

मुख्य अभियंता
केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर अटल नगर

जी-242500879/8

निराशाजनक रहा लोकसभा का पहला सत्र

प्रो. संजय द्विवेदी

भारतीय संसद अपनी गौरवशाली परंपराओं, विमर्शों और संवाद के लिए जानी जाती है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकतांत्रिक बहसों को प्रोत्साहित किया और अपने प्रतिपक्ष के नेताओं डा. राममनोहर लोहिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पीलू मोदी तक को मुग्ध भाव से सुना। राष्ट्र प्रेम ऐसा कि चीन युद्ध के बाद गणतंत्र दिवस की परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को आमंत्रित कर उनकी राष्ट्रभक्ति को सराहा। किंतु लोकसभा के प्रथम सत्र में जो कुछ हुआ,वह संवाद की धारा को रोकने वाला है। इससे संसद विमर्श और संवाद का केंद्र नहीं अखाड़ा बन गयी। राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में जब नेता सदन और प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उनके लगभग दो घंटे के भाषण में विपक्षी सदस्यों ने आसमान सिर पर उठा रखा था। लगातार नारेबाजी से उनका भाषण सुनना मुश्किल था। इसके विपरीत जब पहले दिन नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे,तो उनके भाषण में सत्तारूढ़ दल के प्रधानमंत्री सहित तीन मंत्रियों ने हस्तक्षेप किया। नेता प्रतिपक्ष को बताया गया कि वे सदन के पटल पर गलत तथ्य न रखें। यह दोनों स्थितियां भारतीय राजनीति में बढ़ते अतिवाद को स्पष्ट करती हैं, जहां संवाद संभव नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष पर नेता प्रतिपक्ष द्वारा की गई अनावश्यक टीका-टिप्पणी को भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष की गलत बयानी के लिए बाद में सत्तारूढ़ दल के वक्ता अपने भाषणों में उनके भाषण की चीरफाड़ कर सकते थे। किंतु शीर्ष स्तर से लगातार हस्तक्षेप ने नेता प्रतिपक्ष का मनोबल बढ़ा दिया। वे सत्ता पक्ष को उत्तेजित करने में सफल रहे और पहले दिन के मीडिया विमर्श में उन्हें %सक्रिय नेता प्रतिपक्ष% घोषित कर दिया गया। सेकुलर मीडिया के सेनानियों ने उन्हें %मैन आफ द मैच% घोषित कर दिया। ज़ाहिर है लंबे समय से गंभीर राजनेता की छवि बनाने के लिए आतुर राहुल गांधी के लिए यह अप्रतिम समय था। किंतु पहले दिन की वाहवाही अगले दिन ही धराशाई हो गई जब प्रधानमंत्री के भाषण में दो घंटे तक नारेबाजी चलती रही। देश की जनता दोनों तरह की अतियों के विरुद्ध है। सदन की गरिमा को बचाने के लिए राजनीतिक दलों को कुछ ज्यादा उदार होना चाहिए। लोकसभा के प्रथम सत्र से निकली छवियां बता रही हैं कि आगे भी सब कुछ सामान्य नहीं रहने वाला है। किंतु संसद को अखाड़ा, चौराहे की चर्चा के स्तर पर ले जाने के लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? यह ठीक बात है कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, किंतु सदन में सार्थक और प्रभावी विमर्श खड़ा करना विपक्षी दलों की भी जिम्मेदारी है। अब जबकि विपक्ष अपनी बढ़ी संख्या पर मुग्ध है तो क्या उसे संसदीय मर्यादाओं को छोड़कर अराजकता का आचरण करना चाहिए? सच तो यह है कि सदन के इस तरह चलने से सत्तारूढ़ दल का ही लाभ है। बिना बहस और चर्चा के कानून इसीलिए पास होते हैं क्योंकि संसद का ज्यादातर समय हम विवादों में खर्च कर देते हैं। संसदीय परंपरा रही है कि हर नयी सरकार को प्रतिपक्ष कम से कम छः माह का समय देता है। उसके कार्यक्रम और योजनाएं का मूल्यांकन करता है। पहले दिन से ही सदन को अराजकता की ओर ढकेलना उचित नहीं कहा जा सकता। अपनी लंबी संसदीय प्रणाली में भारत ने अनेक संकटों का समाधान किया है। हमारे संसदीय परंपरा का मूलमंत्र है संवाद से संकटों और समस्याओं का समाधान खोजना। संसद इसी का सर्वोच्च मंच है। यह प्रक्रिया नीचे पंचायत तक जाती है।

इससे सहभागिता सुनिश्चित होती है, सुशासन का मार्ग प्रशस्त होता है। संसद से नीचे के सदनों विधानसभा सभाओं, विधान परिषदों, नगरपालिका, नगर निगमों और पंचायतों को भी सांसदों का आचरण ही रास्ता दिखाता है। लोकसभा के पहले सत्र का लाइव प्रसारण देखते हुए हर संवेदनशील भारतीय जन को ये दृश्य अच्छे नहीं लगे हैं। संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं की रक्षा हमारे सांसद गण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? संसदीय राजनीति के शिखर पर बैठे दायित्ववान सांसदों की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वे अपने आचरण से इस महान संस्था का गौरव बढ़ाने में सहयोगी बनें। नफरतों, कड़वाहटों और संवादहीनता से राजनीति तो संभव है पर राष्ट्रनीति हम न कर पाएंगे।

संसद में टकराव की स्थिति न हो

रशीद किदवई

नयी लोकसभा की शुरुआत बहुत आक्रामक ढंग से हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि दोनों राजनीतिक गठबंधन- सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी इंडिया अलायंस- अभी भी चुनावी मुद्रा में दिख रहे हैं। हमने लंबे लोकसभा चुनाव के दौरान देखा कि दोनों गठबंधनों के प्रमुख नेताओं ने व्यक्तिगत टिप्पणियां की, बयानों में तिरस्कार का भाव था और भाषा तल्ख थी। परिणाम सत्तारूढ़ गठबंधन की आशाओं के अनुरूप नहीं रहा और विपक्ष अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ संसद में हावी होने की कोशिश करता दिखा। आदर्श स्थिति में होना यह चाहिए था कि लोकसभा में बदले समीकरण को देखते हुए दोनों पक्ष एक संतुलित संबंध बनाने का प्रयास करते ताकि टकराव एवं तनातनी की आशंका कम हो, पर ऐसा नहीं हुआ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस में मुख्य वक्ताओं- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी- ने एक तरह से चुनावी बातें ही कहीं और उनके भाषणों में वही तल्खी दिखी, जो चुनाव प्रचार के समय रही थी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले की किसी लोकसभा में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच सीटों का इतना कम फासला कभी नहीं रहा है। साथ ही, इतना कम परस्पर विश्वास और सम्मान का भाव भी पहले कभी नहीं देखा गया। साल 1989 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे और राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे। सिंह कांग्रेस छोड़कर आये थे और उन्होंने राजीव गांधी पर गंभीर आरोप लगाये थे। इसके बावजूद दोनों में कटुता नहीं थी और उनका संवाद भी होता था।

नयी लोकसभा के प्रारंभिक सत्र में यह स्पष्ट दिखा कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को भाजपा नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता अपने को एनडीए गठबंधन के रूप में पेश करते हैं और अपनी संख्या 293 बताते हैं, पर जब विपक्ष की बात आती है, तो वे कांग्रेस के 99 सीटों का ही उल्लेख करते हैं। कुछ निर्दलीय सांसदों के साथ आ जाने से यह संख्या वैसे सौ के ऊपर जा चुकी है। इसी तरह विपक्ष भी भाजपा की संख्या को इंगित करता है, न कि एनडीए गठबंधन के सीटों की। सरकार यह भी अनदेखा करने की कोशिश में है कि विपक्ष अधिक संख्या के साथ लोकसभा पहुंचा है।

दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों के व्यवहार के बारे में कई विश्लेषकों ने कहा है कि उनका झुकाव सत्ता पक्ष की ओर है। इससे दोनों पक्षों के बीच कटुता में वृद्धि ही होगी। राजनीतिक पत्रकार के रूप में मैंने अपने करियर में पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि प्रतिपक्ष के नेता की बातों से विचलित होकर किसी प्रधानमंत्री ने दो बार खड़े होकर आपत्ति जतायी हो। राहुल गांधी के भाषण के दौरान अनेक वरिष्ठ मंत्रियों ने भी ऐसा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने तो अध्यक्ष से संरक्षण तक मांगा।

ये बातें दर्शाती हैं कि सत्ता पक्ष में विपक्ष के नेता के प्रति समुचित सम्मान का भाव नहीं है। इसी तरह, नेता प्रतिपक्ष ने भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं को अपने भाषण में निशाना बनाया, उसे भी सराहा नहीं जा सकता है। इस बार का जनादेश यह है कि प्रधानमंत्री मोदी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करें और मजबूत विपक्ष सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करे। पर शुरुआती दिनों में जो तनाव और टकराव दिखा है, उससे यह आशंका पैदा होना स्वाभाविक है कि क्या यह लोकसभा, और राज्यसभा भी, शांतिपूर्ण ढंग से चल सकेगी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के समय समूचा विपक्ष सदन से बाहर चला गया।

यह बहस अपनी जगह है कि उसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं, पर इस आधार पर विपक्ष पर आक्रामक होना सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि यूपीए-2 की सरकार के समय संसद का 60 प्रतिशत समय हंगामे की भेंट चढ़ गया था। तब लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज थीं और राज्यसभा में यह भूमिका अरुण जेटली निभा रहे थे। उस समय दोनों नेताओं ने तर्क दिया था कि अपनी मांगों को लेकर सदन की कार्यवाही में बाधा डालना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है। इसे भाजपा को नहीं भूलना चाहिए। जिन राज्यों में भाजपा विपक्ष में है, वह भी बहिष्कार करती है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि विपक्ष को बहिष्कार या हंगामे को अपना प्रमुख राजनीतिक हथियार बना लेना चाहिए। संसद और देश के लिए यही उचित होगा कि दोनों पक्ष टकराव का रवैया छोड़कर मिल-जुलकर काम करें, जिसके लिए जनता ने उन्हें निर्वाचित किया है। इस संबंध में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को सकारात्मक भूमिका निभाने की आवश्यकता है। संसद ठीक से चले, इसका उत्तरदायित्व लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का भी है। आम तौर पर सदन की कार्यवाही से किसी सदस्य के भाषण का वह हिस्सा या कुछ ऐसे शब्द हटाये जाते हैं, जो संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं होते है। राजनीतिक बातों को नहीं हटाया जाना चाहिए। इससे बाद में इतिहासकारों और शोधार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पीठासीन अधिकारियों के ऐसा करने से भी दोनों खेमों के बीच तनाव बढ़ेगा। उन्हें अपने आचरण से ऐसा संदेश नहीं देना चाहिए कि वे सत्तारूढ़ खेमे के दबाव में हैं और विपक्ष को उनका संरक्षण नहीं मिल रहा है। नेताओं को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि आवेश में या लापरवाही से वे ऐसी बातें न करें, जिससे माहौल बेमतलब खराब हो। यदि संसद में टकराव की स्थिति जारी रही, जिसकी आशंका बहुत अधिक है, तो अहम मुद्दों पर ठीक से चर्चा संभव नहीं हो सकेगी। इससे किसी को भी फायदा नहीं होगा। भाजपा को जो चुनावी नुकसान हुआ है, उसे उसकी भरपाई करने का प्रयास करना चाहिए। राहुल गांधी या विपक्ष के अन्य नेताओं को घेरते रहने से अच्छा संदेश नहीं जायेगा। विपक्ष को जिस उम्मीद से लोगों ने अधिक सीटें दी हैं, उसके प्रति कांग्रेस और इंडिया अलायंस को गंभीर रहना होगा। सरकार से निरर्थक तनातनी उसके हित में नहीं होगी। विपक्षी नेताओं और सदस्यों पर भी लोगों की उतनी ही नजर होगी, जितनी सत्ता पक्ष पर। संसद में विपक्ष के पास अच्छे और अनुभवी नेता हैं। एनडीए गठबंधन एक दशक से सत्ता में है, उसके यहां भी समर्थ नेताओं की बड़ी संख्या है। इसका फायदा दोनों समूहों को उठाना चाहिए। विपक्ष शैडो कैबिनेट बनाकर एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत कर सकता है। इससे सरकार के कामकाज की ठोस समीक्षा और आलोचना हो सकेगी। सरकार भी अपने स्तर पर विपक्ष को साथ लेने की भरसक कोशिश करे।

एकात्मता के स्वर

ओम सच्चिदानन्द

सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व का वर्णन वारते हुए अश्वेद के नासदीय सूक्त में कहा गया है, तब न सत् था न असत, न परमाणु था न अवकाश, न मृत्यु श्री न अ न रात; म दृष्टा था न दृश्य। उस समय स्पंदनशक्ति-गुक्त यह एक तत्व था। जिसे हम परमात्मा-ईश्वर कहते हैं। सत् चित् (ज्ञान स्वरूप) आनन्दस्वरूप ब्रह्म कहते हैं। तब उसकी इच्छा हुई एको ऽहमबहुस्यामि में एक से अनेक हो जाऊँ। तब महामाया के प्रभाव से प्रकम्पन हुआ और नाव सुनाई दिया। तस्य वाचक: प्रणय: योग 50 1/27 उस ईश्वर का वायक शब्द प्रणव (?) है। भगवान् श्रीकृष्णजी गीता में कहते हैं गिरामस्म्येकमक्षरम 10/25 कि मैं शब्दों में ओंकार हूँ। ओम शब्द अ, उ, म से बना है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्रमश: ओम का प्रतिनिधित्व करते है। त्रिवृद्ब्रह्माक्षरंपरम। श्रीमद्भागवत् 2/1/17 इन तीन मात्राओं से युक्त प्रणव तीनों देवों का ही प्रतिनिधित्व करता है। यह ओम् शब्द सृष्टि का प्रथम अक्षर है इसलिये सभी मांगलिक कार्यों में, वेदपाठों में और मंत्रों में पूर्व ही प्रयुक्त होता है। वह परमात्मा अव्यक्त, अजन्मा, अविनाशी, अप्रमेय, नित्यस्वरूप, अचिन्त्य, अच्छेद्य, अदाद्य, अक्लेद्य, सर्वव्यापी, अचल और कालों का भी महाकाल है। यह भक्तों के लिए साकार और ज्ञानियों-योगियों के लिए वह निराकार है। वही ईश्वर जब-जब होय धरम के हानी तब-तब धरि प्रभु विविध शरीरा.....। राम मा. यदा यदा हि धर्मस्य..... परित्राणाय साधूनां..... भ. गीता 4/7, 8 जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब-तब साधु पुरुषी का उद्धार करने के लिए, पापकर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में उपयुक्त समय पर विविध रूप धारण करता है। वह अपनी विराट सत्ता का दर्शन कभी बालक बनकर यशोदा और कौसल्या माँ को कराता है, कभी अर्जुन, राजा बलि उत्तंक मुनि, तो कहीं दुर्योधन की सभा में। उस परमात्मा के जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं भ. गीता 4/6 जन्म कर्म दिव्य अर्थात् अलौकिक है। न मां कर्माणि लिम्पन्ति भ.गीता 4/14 कर्म के फल में स्पृहा न होने के कारण वह कर्मों में वैधता नहीं है। चातुर्वर्ण्य मयासृष्टं गुण कर्म विभागश:। भ. गीता 4/13 उसी ने गुण और कर्मों के अनुसार चारों वर्णों की सृष्टि की है। ऐसे परमपिता परमात्मा को अनंत बार नमस्कार है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

हंसोपनिषद् (भाग-4)

गतांक से आगे...

इन नादों के प्रभाव से शरीर में विभिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। प्रथम नाद के प्रभाव से शरीर में चिन-चिनी हो जाती है अर्थात् शरीर चिन-चिनाता है। द्वितीय से गात्र भंजन (अंगों में अकड़न) होती है, तृतीय से शरीर में पसीना आता है, चतुर्थ से सिर में कम्पन (कँपकँपी) होती है, पाँचवें से तालु से स्त्राव उत्पन्न होता है, छठे से अमृत वर्षा होती है, सातवें से गूढ़ ज्ञान-विज्ञान का लाभ प्राप्त होता है, आठवें से परावाणी प्राप्त होती है, नौवें से शरीर को अदृश्य करने (अन्तर्धान करने) तथा निर्मल दिव्य दृष्टि की विद्या प्राप्त होती है और दसवें से परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके साधक ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है।

जब मन उस हंस रूप परमात्मा में विलीन हो जाता है, उस स्थिति में संकल्प-विकल्प मन में विलीन हो जाते हैं तथा पुण्य और पाप भी दग्ध हो जाते हैं, तब वह हंस सदा शिवरूप, शक्ति (चैतन्य स्वरूप) आत्मा सर्वत्र विराजमान, स्वयं प्रकाशित, शुद्ध-बुद्ध, नित्य-निरञ्जन, शान्तरूप होकर प्रकाशमान होता है, ऐसा वेद का वचन है। इस रहस्य के साथ इस उपनिषद् का समापन होता है।

महाप्रभु जगन्नाथ की रथयात्रा का पुण्य सौ यज्ञों के बराबर माना जाता है

शुभा दुबे

भारतीय संस्कृति में धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों का विशेष महत्व है। इसी कड़ी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पर्व देशभर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा का मुख्य आयोजन ओडिशा के पुरी नगर में होता है। इस महापर्व में लाखों भक्त भगवान के रथ को खींचने के लिए उत्साह से भरे होते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक भावनाओं का प्रतीक है, बल्कि भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि का भी प्रतीक है। इस पर्व में भगवान जगन्नाथ के रथ की यात्रा को देखने का अनुभव अद्वितीय होता है। लोग भक्ति और श्रद्धा के साथ रथ को खींचते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को खासतौर पर ओडिशा के पुरी नामक स्थान और गुजरात के द्वारका पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। पुरी में श्री जगदीश भगवान को सपरिवार विशाल रथ पर आरुढ़ कराकर भ्रमण करवाया जाता है फिर वापस लौटने पर यथास्थान स्थापित किया जाता है। यह उत्सव अद्वितीय होता है। इस अवसर पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां एकत्र होते हैं। इस उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं का भक्ति भाव देखते ही बनता है क्योंकि जिस रथ पर भगवान सवारी करते हैं उसे घोड़े या अन्य जानवर नहीं बल्कि श्रद्धालुगण ही खींच रहे होते हैं।

रथयात्रा के दिन भगवद भक्त व्रत रखते हैं और उत्सव मनाते हैं। पुरी में जिस रथ पर भगवान की सवारी चलती है वह विशाल एवं अद्वितीय है। वह 45 फुट ऊंचा, 35 फुट लंबा तथा इतना ही चौड़ाई वाला होता है। इसमें सात फुट व्यास के 16 पहिये होते हैं। इसी तरह बालभद्र जी का रथ 44 फुट ऊंचा, 12 पहियों वाला तथा सुभद्रा जी का रथ 43 फुट ऊंचा होता है। इनके रथ में भी 12 पहिये होते हैं। प्रतिवर्ष

नए रथों का निर्माण किया जाता है। भगवान मंदिर के सिंहद्वार पर बैठकर जनकपुरी की ओर रथयात्रा करते हैं। जनकपुरी में तीन दिन का विश्राम होता है जहां उनकी भेंट श्री लक्ष्मीजी से होती है। इसके बाद भगवान पुन: श्री जगन्नाथ पुरी लौटकर आसनरुढ़ हो जाते हैं।

भारत के मुख्य पर्वों में दस दिवसीय रथयात्रा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भगवान श्रीकृष्ण के अवतार जगन्नाथ की रथयात्रा का पुण्य सौ यज्ञों के बराबर माना जाता है। यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाती है। जगन्नाथ जी का रथ गरुड़ध्वज या कपिलध्वज कहलाता है। रथ पर जो ध्वज है, उसे त्रैलोक्यमोहिनी या 'नंदीघोष' रथ कहते हैं। बलराम जी का रथ तलध्वज के नाम से पहचाना जाता है। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। जिस रस्सी से रथ खींचा जाता है वह वासुकी कहलाता है। सुभद्रा का रथ पद्मध्वज कहलाता है। रथ ध्वज नर्दंबिक कहलाता है। इसे खींचने वाली रस्सी को स्वर्णचूडा कहते हैं। भगवान की रथयात्रा में सभी वर्गों के लोग शामिल होते हैं। रथयात्रा आरंभ होने से पहले पुराने राजाओं के वंशज पारंपरिक ढंग से सोने के हत्थे वाली झाड़ू से ठाकुर जी के प्रस्थान मार्ग को साफ करते हैं। इसके बाद मंत्रोच्चार एवं जयघोष के साथ रथयात्रा शुरू होती है। सर्वप्रथम बलभद्र का रथ तालध्वज प्रस्थान करता है। थोड़ी देर बाद सुभद्रा की यात्रा शुरू होती है। अंत में लोग जगन्नाथ जी के रथ को बड़े ही श्रद्धापूर्वक खींचते हैं।

2024 में कैसे बदल रही वैश्विक राजनीति

अभिनय आकाश

2024 चुनावी साल है। इस वर्ष 80 से अधिक देशों में चुनाव होने हैं, उनमें से कुछ पहले ही संपन्न हो चुके हैं। इनमें कुछ सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली, सबसे अधिक आबादी वाले, सबसे अधिक सत्तावादी राष्ट्र शामिल हैं। इनमें से कई चुनाव लोकतंत्र की सीमाओं का परीक्षण तो अन्य केवल रबर-स्टैंपिंग प्रैक्टिस सरीखे भी नजर आए। वोटिंग के लिहाज से दुनिया के दो सबसे बड़े चुनाव समझे जाने वाले भारत और यूरोपीयन यूनियन के चुनाव भी इस साल ही हुए हैं। एक तरफ जहां ईयू में सेंटरिस्ट पार्टियों के हाथ से सत्ता राइट विंग पार्टियों के पास चली गई। वहीं भारत में प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुए। संयुक्त राष्ट्र में वीटो रखने वाले देश अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन में भी इस साल ही चुनाव है। ईरान में भी वोट डाले जा रहे हैं।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद फ्रांस में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी दक्षिणपंथी पार्टी के सरकार बनाने की प्रबल उम्मीद जताई जा रही है। पहले चरण के संसदीय चुनाव के बाद मरीन ले पेन के नेतृत्व में देश की धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली अपनी बढ़त से खुश नजर आ रही है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की पार्टी इस बार तीसरे स्थान पर खिसक गई है। मरीन ल पेन खुद को राष्ट्रवादी बताती हैं और उन्होंने यह वादा किया था कि अगर वह सत्ता में आती है तो सबसे पहले फ्रांस में इमीग्रेशन से जुड़े नियमों को सख्त बनाएंगे। शरणार्थियों की संख्या में

कमी करेंगे। कट्टर इस्लामिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और फ्रांस को यूरोपीय यूनियन से निकालने पर भी विचार किया जाएगा। मरिन ले पेन हैं को पहले राउंड के चुनाव में कुल 23.15 फीसद वोट मिले हैं। नेशनल रैली का नस्लवाद और यहूदी-विरोधी भावना से पुराना संबंध है और यह फ्रांस के मुस्लिम समुदाय की विरोधी मानी जाती है। इमैनुएल मैक्रों को उदारवादी नेता माना जाता है। वो यूरोप के साथ फ्रांस के संबंधों को मजबूत बनाना चाहते हैं। इस साल जून की शुरुआत में यूरोपीय संसद के चुनाव में नेशनल रैली से मिली करारी शिकस्त के बाद मैक्रों ने फ्रांस में मध्यावधि चुनाव की घोषणा की थी देश में 4.95 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं जो फ्रांस की संसद के प्रभावशाली निचले सदन नेशनल असेंबली के 577 सदस्यों को चुनेंगे।

अमेरिका में अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों को लोग भूल जाते हैं। हारे हुए उम्मीदवार कभी भी दोबारा कमबैक नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बार रिपब्लिकन पार्टी के केस में अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है और ट्रंप की खासी धमक नजर आ रही है। चार बरस पहले ट्रंप ने राष्ट्रपति का पहला कार्यकाल विवादों के बीच समाप्त किया था। 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हुई हिंसा अमेरिकी इतिहास का सबसे दुखद हिस्सा बन चुका है। एक बार फिर ट्रंप और बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव के लिए आमने सामने हैं। दोनों नेताओं के बीच बीते दिनों 90 मिनट की बहस हुई। इस दौरान अर्थव्यवस्था, आव्रजन, विदेश नीति, गर्भपात और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन और ट्रंप के बीच वार पलटवार देखने को मिला। एसएसआरएस द्वारा आयोजित सीएनए फ्लैश सर्वेक्षण के अनुसार डिबेट देखने वाले रजिस्टर्ड लोगों में से 67 प्रतिशत ने ट्रंप के प्रदर्शन को बेहतर कहा जबकि 33 फीसदी लोग इस मामले में बाइडेन के साथ दिखे।

ब्रिटेन में चार जुलाई को हुए आम चुनाव की अभी तक मतगणना में लेबर पार्टी ने बहुमत के लिए पर्याप्त सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वहीं, निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हार स्वीकार करते हुए लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर को बधाई दी है। कंजर्वेटिव पार्टी को अब तक की सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ रहा है। कीर स्टारमर की पर्सनालिटी सुनक से एकदम उलट है। भारतवंशी सुनक जहां खुद को धार्मिक बताते रहे हैं, वहीं स्टार्मर भगवान में यकीन नहीं करते। वे सुनक की तरह अरबपति भी नहीं हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि जब हिंदू वोटर्स से जुड़े संगठनों ने लेबर पार्टी को वोट न देने की कसम खाई थी। 2020 में कीर स्टार्मर लेबर पार्टी के नेता बने तो उन्होंने हिंदू वोटरों की नाराजगी खत्म करने की कोशिश की और कश्मीर मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड बदला।

ईरान में पिछले महीने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के मारे जाने के बाद देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं जिसमें मुकाबला कट्टरपंथी परमाणु वार्ताकार सईद जलीली और सुधारवादी मसूद पजशकियान के बीच है। इससे पहले 28 जून को मतदान के शुरुआती दौर में किसी भी उम्मीदवार को 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट नहीं मिले जिसके कारण दोबारा मतदान कराए जा रहे हैं। मतदाताओं को कट्टरपंथी पूर्व परमाणु वार्ताकार सईद जलीली और हार्ट सर्जन तथा लंबे समय से संसद सदस्य रहे मसूद पजशकियान के बीच चुनाव करना है। 28 जून को हुए मतदान में उदारवादी नेता मसूद पजशकियान ने 10.4 मिलियन यानी 42 फीसद वोट हासिल किए हैं। वहीं कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को महज 9.4 मिलियन यानी 38.6 फीसद वोट ही मिले हैं। अगर रन ऑफ राउंड में भी मसूद पजशकियान जीतते हैं तो ये मध्य पूर्व में बड़ा बदलाव ला सकता है। तबरीज से सांसद मसूद पजशकियान की पहचान सबसे उदारवादी नेता के रूप में रही है। ईरानी मीडिया ईरान वायर के मुताबिक लोग पेजेशकियन को रिफॉर्मिस्ट के तौर पर देख रहे हैं। उन्हें पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी का करीबी माना जाता है। पश्चमी देशों संग बेहतर रिश्ता बनाने के हिमायती भी हैं।

आज का इतिहास

1946 मदर फ्रांसेस ज़ेवियर कैब्रिनी एक संत के रूप में बेकनॉनिज़ किए गए पहले अमेरिकी बन गए।
1963 दक्षिण वियतनाम के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार, नगो दीन्ह नु, के भाई और दक्षिण वियतनाम के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार, एनगो दीन्ह दीम ने बौद्ध धर्मगुरुओं के दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे अमेरिकी पत्रकारों के एक समूह पर हमला किया।
1978 सोलोमन द्वीपों को यूनाइटेड किंगडम से अपनी स्वतंत्रता मिली। यह एक स्वायत्त देश है जिसमें कई द्वीपों का समूह शामिल है। यह पापुआ न्यू गिनी के पास स्थित है। यह एक संवैधानिक राजतंत्र है।
1978 सोलोमन द्वीप ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की। यूरोपियों ने 1567 में इस द्वीप समूह की खोज की थी।
1978 ग्रेट ब्रिटेन ने सोलोमन द्वीप को स्वतंत्रता प्रदान की।
1979 सोवियत संघ ने पूर्वी कजाख में परमाणु परीक्षण किया।
1980 ईरान में शरिया कानून लागू हुआ।
1983 सोवियत प्रीमियर यूरी एंड्रोपोव को एक पत्र लिखने के बाद, अमेरिकी छात्रा समांथा स्मिथ ने सोवियत संघ के आसारोपोव के निजी मेहमान का दौरा किया, जिसे अमेरिका के यंगेस्ट एंबेसडर के रूप में जाना जाता है।
1985 बोरिस बेकर सबसे कम उम्र के विंबलडन विजेता बने। उन्होंने 17 साल की उम्र में विंबलडन चैंपियनशिप जीती थी। वह एक जर्मन टेनिस खिलाड़ी थे और कई टेनिस चैंपियनशिप जीत चुके थे। उन्हें अपने समय के दौरान दुनिया में नंबर 1 के रूप में भी स्थान दिया गया था। वर्तमान में वह कोचिंग संसार नं। 1 नोवाक जोकोविच।
1994 पूर्व उत्तरी यमन के सैनिकों ने एडेन पर कब्जा कर लिया, येमेनी गृह युद्ध को समाप्त कर दिया।
1994 यमन में 1994 के गृह युद्ध : उत्तरी यमन में सैनिकों ने एडन पर कब्जा कर किया।

धर्मनिरपेक्ष भारत को यूसीसी से नहीं शरिया से चलाने की जिद्द क्यों?

संजय सक्सेना

मोदी सरकार द्वारा पहली जुलाई से देश में भारतीय न्याय संहिता लागू किये जाने के बाद अब समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) का मुद्दा गरमाने लगा है, जिस तरह से मोदी सरकार के मंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यूसीसी के पक्ष में बयानबाजी कर रहा हैं उससे यूसीसी विरोधियों के भी सुर मुखर होने लगे हैं। सुन्नी पर्सनल लॉ बोर्ड तो पहले से ही यूसीसी का विरोध कर रहा था, अब शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएसपीएलबी) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समान नागरिक संहिता उन्हें किसी दशा में स्वीकार नहीं है। उनकी कौम देश के कानून से नहीं चलेगी, बल्कि शरीयत कानून को ही मानेगी। बोर्ड ने धमकी वाले अंदाज में कहा है कि मोदी सरकार यूसीसी बनाने की प्रक्रिया को रोक दे। इसके साथ ही बोर्ड की तरफ से चेतावनी भी दी गई कि यदि मोदी सरकार ने हमारा अनुरोध नहीं माना तो मोहर्रम के बाद आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे। बोर्ड के यह तेवर तब हैं जबकि भारतीय संविधान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी नागरिकों के लिये समान कानून की बात लम्बे समय से कहता रहा है।अलग-अलग मौकों पर देश की तमाम अदालतें सरकार से यूसीसी लागू करने के लिये कानून बनाने की बात भी कह चुकी हैं। वैसे भी एक धर्मनिरपेक्ष देश में सबके लिये एक जैसे कानून में कोई बुराई नजर नहीं आती है।

गौरतलब है कि हाल के वर्षों में समान नागरिक संहिता पर सियासी और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर ही माहौल गर्म रहा है। एक ओर जहाँ देश की बहुसंख्यक आबादी समान नागरिक संहिता को लागू करने की पुरजोर मांग उठाती रही है, वहीं अल्पसंख्यक वर्ग इसका विरोध करता रहा है। इसी के मद्देनजर इस मुद्दे पर हर चुनाव में खूब राजनीति होती रही है, वहीं चुनाव बाद इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, लेकिन लगता है कि अब मोदी सरकार इस पर बड़ा निर्णय लेने का मन बना चुकी है। यूसीसी से सबसे अधिक फायदा महिलाओं को होगा। क्योंकि आज भी किसी भी समाज और कौम में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार मिलना रेगिस्तान में नखिलस्तान से कम नहीं है, लेकिन यूसीसी लागू होने से महिलाओं के सामने कदम-कदम पर आने वाली चुनौतियाँ का ग्राफ थोड़ा कम हो सकता हैं। मगर चिंता की बात यह है कि एक तरफ जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय नागरिक संहिता को अनुच्छेद 25 का हनन मानते हैं, वहीं इसके झंडाबरदार समान नागरिक संहिता की कमी को अनुच्छेद 14 का अपमान बता रहे हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सांस्कृतिक विविधता से इस हद तक समझौता किया जा सकता है कि समानता के प्रति हमारा आग्रह क्षेत्रीय अखंडता के लिए ही खतरा बन जाए? क्या एक एकीकृत राष्ट्र को 'समानता' की इतनी जरूरत है कि हम विविधता की खूबसूरती की परवाह ही न करें? इसका जबाव हां में है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि देश का संविधान देशवासियों को कुल मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें भाषा और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार, जमा होने संघ या यूनियन बनाने, आने-जाने, निवास करने और कोई भी

जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार (इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ भिन्नता पूर्ण संबंध सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के अधीन दिए जाते हैं)। बोलने, खाने पीने और अपने विचार व्यक्त करने की हमें आजादी है, लेकिन इसी आजादी का जब लोग गलत फायदा उठाने लगते हैं तो देश की संप्रभुता पर खतरा मंडराने लगता है।उस समय जनता को अधिकार के साथ उनकी जिम्मेदारी से भी अवगत कराया जाता है। समान नागरिक संहिता इसी क्रम की एक कड़ी मात्र है।

सवाल उठता है कि अगर हम सदियों से अनेकता में एकता का नारा लगाते आ रहे हैं तो, कानून में भी एकरुपता से आपत्ति क्यों? क्या एक संविधान वाले इस देश में लोगों के निजी मामलों में भी एक कानून नहीं होना चाहिए? अगर अब तक समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोशिश संजीदगी से नहीं हुई है तो, इसके पीछे अल्पसंख्यक वोट बैंक की सियासत तो नहीं है? बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि 'राज्य, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा'।

समान नागरिक संहिता में किसी के रीति-रिवाज पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन शादी, तलाक तथा जमीन-जायदाद के बँटवारे आदि में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होता है। अभी देश में जो स्थिति है उसमें सभी धर्मों के लिए अलग-अलग नियम हैं। संपत्ति, विवाह और तलाक के नियम हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए अलग-अलग हैं। इस समय देश में कई धर्म के लोग विवाह, संपत्ति और गोद लेने आदि में अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना-अपना पर्सनल लॉ है जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं।

गौरतलब हो संविधान निर्माण के बाद से ही समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग उठती रही है। लेकिन, जितनी बार मांग उठी है उतनी ही बार इसका विरोध भी हुआ है। समान नागरिक संहिता के हिमायती यह मानते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव करने की मनाही और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और निजता के संरक्षण का अधिकार लोगों को दिया गया है। लेकिन, महिलाओं के मामले में इन अधिकारों का लगातार हनन होता रहा है। बात चाहे तीन तलाक की हो, मंदिर में प्रवेश को लेकर हो, शादी-विवाह की हो या महिलाओं की आजादी को लेकर हो, कई मामलों में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। इससे न केवल लैंगिक समानता को खतरा है बल्कि, सामाजिक समानता भी सवालों के घेरे में है। जाहिर है, ये सारी प्रणालियाँ संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। लिहाजा, समान नागरिक संहिता के झंडाबरदार इसे संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं।

दूसरी तरफ, अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिम समाज समान नागरिक संहिता का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा जाता है कि संविधान ने देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इसलिये, सभी पर समान कानून थोपना संविधान के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। मुस्लिमों के मुताबिक उनके निजी कानून उनकी धार्मिक आस्था पर आधारित हैं इसलिये समान नागरिक संहिता लागू कर उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए।

दरअसल, समान नागरिक संहिता को लागू करने की पूरजोर मांग उठने के बाद भी इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका है। कई मौके ऐसे आए जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी समान नागरिक संहिता लागू न करने पर नाखुशी जताई है। 1985 में शाह बानो केस और 1995 में सरला मुदगल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समान नागरिक संहिता पर टिप्पणी से भी इस मुद्दे ने जोर पकड़ा था, जबकि पिछले वर्ष ही तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद भी इस मुद्दे को हवा मिली। लेकिन, सवाल है कि इस मसले पर अब तक कोई ठोस पहल क्यों नहीं हो सकी है? दरअसल, भारत का एक बहुल संस्कृति वाला देश होना इस रास्ते में बड़ी चुनौती है। हिंदू धर्म में विवाह को जहाँ एक संस्कार माना जाता है, वहीं इस्लाम में इसे एक अनुबंध माना जाता है। ईसाइयों और पारसियों के रीति- रिवाज भी अलग-अलग हैं।

मौजूदा वक्त में गोवा और उत्तराखंड दो ऐसे राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। जाहिर है, इसके लिए काफी प्रयास किए गए होंगे। इसलिए यह कहना गलक नहीं होगा कि दूसरे राज्यों में भी अगर कोशिश की जाती है तो, इसे लागू करना मुमकिन हो सकता है।दूसरी ओर वोटबैंक की राजनीति भी इस मुद्दे पर संजीदगी से पहल न होने की एक बड़ी वजह है। एक दल जहाँ समान नागरिक संहिता को अपना एजेंडा बताता रहा है, वहीं दूसरी पार्टियाँ इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरकार की राजनीति बताती रही हैं। जाहिर है, एक दल को अगर वोट बैंक के खिसक जाने का डर है तो, दूसरे को वोट बैंक में सेंध लगाने की फिक्र है। दरअसल, सियासी दलों का यह डर पुराना है।

बता दें यूसीसी की तरह ही 1948 में जब हिन्दू कोड बिल संविधान सभा में लाया गया, तब देश भर में इस बिल का जबरदस्त विरोध हुआ था। बिल को हिन्दू संस्कृति तथा धर्म पर हमला करार दिया गया था। सरकार इस कदर दबाव में आ गई कि तत्कालीन कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर को पद से इस्तीफा देना पड़ा। यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक दल समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर जोखिम नहीं लेना चाहता। हमें समझना होगा कि जब हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होगा तो, देश के सियासी दल वोट बैंक वाली सियासत भी नहीं कर सकेंगे और भावनाओं को भड़का कर वोट मांगने की रिवायत पर भी लगाम लग सकेगा।

ब्रिटेन में जीतकर भी हार गए भारतवंशी ऋषि सुनक

विवेक शुक्ला

ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री और सारी दुनिया के भारतवंशियों के प्रिय ऋषि सुनक अपनी कंजरवेटिव पार्टी को ब्रिटेन की संसद (हाउस ऑफ कॉमन्स) के लिए हुए चुनाव में जीत दिलवाने में नाकाम रहे। हालांकि वे अपनी सीट जीतने में सफल रहे। ऋषि सुनक ने उस परंपरा को ही आगे बढ़ाया था जिसका 1961 में श्रीगणेश सुदूर कैरीबियाई टापू देश गयाना में छेदी जगन ने किया था। वे तब गयाना के प्रधानमंत्री बन गए थे। उनके बाद मॉरीशस में शिवसागर रामगुलाम से लेकर अनिरुद्ध जगन्नाथ, त्रिनिदाद और टोबैगो में वासुदेव पांडे, सूरीनाम में चंद्रिका प्रसाद संतोखी, अमेरिका में कमला हैरिस वगैरह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनते रहे। ये सभी उन मेहनतकशों की संतानें रही हैं, जिन्हें गोरे दुनियाभर में लेकर गए थे ताकि वे वहां खेती करें। सुनक के पुरखे पंजाब से करीब 80 साल पहले कीनिया चले गए थे और वहां से वे ब्रिटेन जाकर बसे। बेशक, आगे भी छेदी जगन और सुनक की तरह भारतवंशी भारत के बाहर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। बहरहाल, कीर स्टार्मर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्योंकि उनकी लेबर पार्टी को चुनाव में भारी जीत मिली है। प्रधानमंत्री सुनक ने उत्तरी इंग्लैंड में रिचमंड एवं नॉर्थलेरटन सीट पर 23,059 वोट के अंतर के साथ दोबारा जीत हासिल की। ब्रिटेन की निवर्तमान संसद में भारतीय मूल के 15 सांसद थे, जबकि ब्रिटिश मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस बार भारतीय मूल के पिछली बार के मुकाबले अधिक सांसद जीते हैं। इसमें लेबर पार्टी और कंजरवेटिव पार्टी, दोनों दलों के सांसदों का समावेश है। जीतने वालों में ऋषि सुनक के अलावा शिवानी राजा, प्रीति पटेल और नवेंदु मिश्रा जैसे नाम शामिल हैं। संसद का चुनाव कनाडा का हो, ब्रिटेन का हो या फिर किसी अन्य लोकतांत्रिक देश का, भारतीय उसमें अपना असर दिखाने से पीछे नहीं रहते। उन्हें सिर्फ वोटर बने रहना नामंजूर है। वे चुनाव लड़ते हैं। करीब दो दर्जन देशों में भारतवंशी संसद तक पहुंच चुके हैं। हिंदुस्तानी सात समंदर पार मात्र कमाने-खाने के लिए ही नहीं जाते। वहां पर जाकर हिंदुस्तानी राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी करते हैं। अगर यह बात न होती तो लगभग 22 देशों की पार्लियामेंट में 182 भारतवंशी सांसद न होते। दक्षिण अफ्रीका को ही लें। वहां पिछली मई में संसद के लिए हुए चुनाव में भी भारतीय मूल के बहुत से उम्मीदवार विभिन्न राजनीतिक दलों से अपना भाग्य आजमा रहे थे। उन्होंने संसद और प्रांतीय असेंबलियों में भी जीत दर्ज की। अब कुछ महीनों के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव है। उम्मीद है कि वहां एक बार फिर से भारतवंशी कमला हैरिस उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएंगी।

आपराधिक मानसिकता पर अंकुश ही कानून की सफलता

पूरन चंद सरीन

देश ने अंग्रेजों के जमाने के कानून बदल दिए हैं। क्या केवल नाम बदला है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न आज बहस का विषय है? इन्हें न्याय का पर्याय बताया जा रहा है। क्या यह समझा जाए कि क्योंकि वे गुलामी की निशानी थे इसलिए बदलाव जरूरी था?

इसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि समाज में यदि किसी ने कोई गलती की है और छोटे या बड़े किसी भी स्तर का अपराध है, उसके लिए दंड अनिवार्य है। इसकी विधि क्या है। नियम है कि इस पर विचार करने, निर्णय तक पहुंचने और फिर फैसला सुनाने तथा उस पर अमल करने के लिए नियुक्त पुलिस, दंडाधिकारी और न्यायाधीश के सामने एक विकल्प रहता है कि वे कानून की धाराओं के अनुसार आचरण करने या अपने विवेक अर्थात समझ के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। यही वास्तविक मुद्दा है जिस पर न पहले और न अब लागू कानूनों में तनिक भी ध्यान दिया गया है। यह आवश्यक था पर इसे नहीं किया गया।

कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है; 2 व्यक्ति एक ही कानून, मान लीजिए, मनी लांड्रिंग के अंतर्गत पकड़े जाते हैं। सब कुछ समान है लेकिन एक को जमानत मिल जाती है, दूसरे को नहीं। एक न्यायाधीश जमानत देता है तो दूसरा उच्च न्यायालय में बैठकर उस पर रोक लगा देता है। हैरानी की बात है। एक और उदाहरण है। एक व्यक्ति को अपनी युवावस्था में किसी अपराध के लिए लंबी सजा सुना दी जाती है। 5, 10, 15, या 20 नहीं अनेकों बार पाया जाता है कि यह व्यक्ति तो निरपराध था, उसने तो अपराध किया ही नहीं था। मतलब यह कि किसी ने तो अपराध

किया था और वह आजाद घूम रहा था और निर्दोष सजा काट रहा था। वर्षों बाद निर्णय होता है कि सजा गलत थी। वह सलाखों से बाहर आता है। तब तक असली अपराधी न्याय तंत्र की पहुंच से बाहर जा चुका होता है।

प्रश्न उठता है कि क्या किसी भी न्यायाधीश का यह कहना पर्याप्त है कि महोदय ने अपने विवेक के आधार पर तब निर्णय किया था या अब किया है? उनके इस विवेक ने न्याय की बखिया उधेड़ दी और उन पर आंच तक नहीं आ सकती, उनके निर्णय पर प्रश्न नहीं उठ सकता क्योंकि वे अपनी समझ से फैसला करते हैं, यदि किसी ने कोशिश की तो अदालत की अवमानना होगी। आरोपी, वकील और न्यायाधीश तक सभी इस प्रक्रिया की वास्तविकता से परिचित हैं। यह विवेकपूर्ण आचरण सही है या खरीदा गया है, यह सवाल उठने से पहले ही दब जाता है। एक ओर कोई नर्क की यातना झेल रहा है, उसके पक्ष में गवाही देने वालों पर मौत का साया मंडराता रहता है और दूसरी ओर असली गुनाहगार सीना तानकर चल रहा है। मुकद्दमे और सजा की त्रासदी से टूट गए व्यक्ति के गंवाए वर्षों का कोई मूल्य नहीं, मामूली क्षतिपूर्ति तक नहीं और न्याय की दुहाई देने वालों के लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं।

यह स्थिति आजादी से पहले थी और बदस्तूर आज तक चली आ रही है। प्रश्न उठता है कि जिसने सजा दी थी और जिसने अब रिहाई का हुक्म सुनाया, क्या उनकी जांच-पड़ताल और उनसे कानूनन पूछताछ नहीं होनी चाहिए ? इसका कोई प्रावधान न पहले था और न अब है। स्वतंत्र भारत में न्याय प्रणाली की यह मजबूरी क्या समाप्त हो पाएगी?

इन कानूनों को न्याय कहा गया है। व्यापक अर्थों में यह कहा जा सकता है कि न्याय वही जो आपराधिक मानसिकता से मुक्त रखने का काम करे। अपराध की तो सजा निश्चित हो गई लेकिन उससे पहले गंभीर चिंतन का विषय यह होना चाहिए था कि क्या कानूनों के माध्यम से समाज की उस प्रवृत्ति पर रोक लगती है जो किसी को अपराध करने के प्रति उकसाती है, दूसरे का अधिकार छीनने की इच्छा पैदा करती है, दबंगई पर रोक लगाना तो दूर, उसे पालने-पोसने का काम करती है? यही नहीं धन और बल से कुछ भी करने और किसी को भी प्रताड़ित करने की सोच को विकसित करती है।

इन कानूनों में कुछ मामलों में सजा को समाज सेवा के दायरे में रखने की बात कही गई है। यह सेवा क्या और कैसी होगी, इसका कोई विवरण नहीं है? समाज सेवा के नाम पर तो अधिकतर राजनीतिक क्षेत्र को चुना जाता है। क्या अपराधियों से इसके माध्यम से राजनीति में उतरने की अपेक्षा है। पहले से ही इसमें अपराधियों को प्रवेश मिल रहा है और वे विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री तक बने बैठे हैं। क्या समाज सेवा के पर्दे में ऐसे लोगों की एक नई खेप तैयार करने का इरादा तो नहीं?

पुलों का ढहना शासन-तंत्र की भ्रष्टता का प्रमाण

ललित गर्ग

बिहार में एक पखवाड़े के भीतर लगभग एक दर्जन छोटे-बड़े पुलों के ध्वस्त होने की घटनाएं हैरान करने के साथ-साथ चिंतित करने वाली हैं। जैसी खबरें हैं, अकेले बुधवार, यानी 3 जुलाई को ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में पांच पुल-पुलिया धराशायी हो गए। इनमें सिवान में छाड़ी नदी पर बने दो पुल शामिल हैं। इससे पहले दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल-1 पर छत गिरने की घटना से भी हर कोई हैरान है। इस हादसे के कारण अनेक वाहन क्षतिग्रस्त हुए एवं एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए थे। सभी को इस बात की हैरानी हो रही है कि देश के सबसे प्रमुख हवाईअड्डे पर इस तरह का हादसा कैसे हो सकता है? मुंबई में भी घाटकोपर का होर्डिंग गिरना 14 लोगों की मौत का कारण बना था। इन पुलों के गिरने एवं अन्य सरकारी निर्माणों के ध्वस्त होने की घटनाओं ने एक बार फिर यही साबित किया है कि निर्माण कार्यों में फैले व्यापक भ्रष्टाचार और शासन तंत्र में बैठे लोगों की मिलीभगत के बीच ईमानदारी, नैतिकता, जिम्मेदारी या संवेदनशीलता जैसी बातों की जगह नहीं है। आज हमारी व्यवस्था चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, धार्मिक हो, औद्योगिक हो, शैक्षणिक हो, चरमरा गई है, दोषग्रस्त हो गई है। उसमें दुराग्रही इतना तेज चलते हैं कि ईमानदारी बहुत पीछे रह जाती है। जो सद्प्रयास किए जा रहे हैं, वे निष्फल हो रहे हैं। पुल के गिरने से जितने पैसों की बर्बादी हुई, उसकी भरपाई आखिर किससे कराई जाएगी? बिहार में पुल गिरने की ताजा घटनाएं कोई पहली नहीं है। इससे पहले पिछले साल भर में सात पुलों के ढह जाने की खबरें आईं थी।

जाहिर है, इन पुलों के ढहने एवं गिरने से कई गांवों का आपस में सीधा संपर्क टूट गया है और मानसून के मौसम में उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। बरसात के मौसम में जर्जर ढांचों के गिरने की घटनाएं ज्यादा घटती हैं और इसीलिए सभी राज्यों में स्थानीय प्रशासन मानसून आने से पहले ही उनकी पहचान कर उनका इस्तेमाल प्रतिबंधित कर देता है। मगर पुल कोई रिहाइशी इमारत नहीं, जिसमें चंद परिवार या कुछ लोग रहते हों, और जिसे एहतियातन खाली करा लिया जाए। ये पुल ग्रामीण लोगों के जीवन की

अनिवार्यता एवं जीवनरेखाएं हैं। उच्च तकनीक और प्रौद्योगिकी के मौजूदा समय में उच्च लागत के बावजूद छोटी नदियों और नहरों पर बनने वाले पुल भी यदि चंद वर्षों में या बनते ही धराशायी हो जाएं, तो इसको कुदरती कहर का नतीजा नहीं, आपराधिक मानवीय लापरवाही, भ्रष्टाचार एवं सरकारी धन का दुरुपयोग ही मानना चाहिए। बिहार में सिवान की जिस नदी पर दो पुलों के ढहने की घटना घटी है, वह मृत हो चुकी थी और उसे जल-जीवन हरियाली अभियान के तहत पुनर्जीवित किया गया था। निस्संदेह, इसके लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन सराहना के पात्र हैं। आखिर इस नदी के जिंदा होने से हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई को बल मिला है। मगर क्या उसी तंत्र को यह भी नहीं सुनिश्चित करना चाहिए था कि जो पुल जर्जर अवस्था में हैं, उनका विकल्प भी साथ-साथ तैयार किया जाए?

इस तरह बार-बार पुलों का गिरना एवं ध्वस्त होना सरकार में गहरे पैठ चुके भ्रष्टाचार, लापरवाही एवं रिश्वतखोरी को उजागर करता है। आजादी के अमृत-काल में पहुंचने के बाद भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी हमारी व्यवस्था में तीव्रता से व्याप्त है, अनेक हादसों एवं जानमाल की हानि के बावजूद भ्रष्ट हो चुकी मोटी चमड़ी पर कोई असर नहीं होता। ये पुल हादसें एवं ध्वस्त होने की घटनाएं बिहार में सरकारी भ्रष्टाचार के चरम पर होने को ही बल देती है। ऐसा नहीं है कि बिहार में ही ऐसे हादसें हो रहे हैं। गुजरात के मोरबी पुल हादसे को लोग अब भी नहीं भूले हैं। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। सात साल पहले कोलकाता में विवेकानंद पुल के ढहने से 26 लोगों की मौत की घटना भी सबको याद होगी। सिर्फ बिहार में पुलों का यूं ढहते जाना ही चिंता की बात नहीं है, दूसरे तमाम राज्यों से भी चमचम सड़कों पर बनते गड्ढ़ों और नए निर्माण के दरकने की खबरें लगभग रोजाना सुर्खियां बटोर रही हैं। इसलिए बेहतर होगा कि तमाम सार्वजनिक निर्माण में पारदर्शिता, ईमानदारी एवं आधुनिक स्थापित मानकों की गारंटी सुनिश्चित की जाए और इसमें किसी किस्म की कोताही बरतने वाले की जिम्मेदारी तय हो। देश भर में तमाम पुराने पुलों की समीक्षा के साथ-साथ उनके रखरखाव या वैकल्पिक पुल के निर्माण को लेकर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

इतना तय है कि ये सभी पुल अगर भरभरा कर गिर रहे हैं तो इनकी डिजाइन गलत होने से लेकर उसमें उपयोग होने वाली सामग्री के घटिया होने का भी साफ संकेत है। लेकिन जिस तरह सरकार इन एवं ऐसे पुलों की गुणवत्ता और जोखिम का अध्ययन करा रही थी, क्या उसके निर्माण के दौरान या उससे पहले डिजाइन सहित उसके हर कसौटी पर बेहतर होने के लिए जांच कराना सुनिश्चित नहीं कर सकती थी? यह तय है कि इन पुलों के निर्माण में व्यापक खामियां थीं और वे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गये। सवाल है कि जब सरकार किसी कंपनी को पुल निर्माण की जिम्मेदारी सौंपती हैं, उससे पहले क्या गुणवत्ता की कसौटी पर पूरी निर्माण योजना, डिजाइन, प्रक्रिया, सामग्री, समय-सीमा और संपूर्णता को सुनिश्चित किया जाना जरूरी समझा जाता? देश में भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त है, विशेषत: राजनीतिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने देश के विकास को अवरूद्ध कर रखा है। यही कारण है कि पुल या दूसरे निर्माण-कार्यों के लिए रखे गए बजट का बड़ा हिस्सा कमीशन-रिश्वतखोरी की भेंट चढ़ जाता है। इसका सीधा असर निर्माण की गुणवत्ता पर पड़ता है। निर्माण घटिया होगा तो फिर उसके धराशायी होने की आशंका भी बनी रहती है। हादसों का एक बड़ा कारण जांच में दोषी और जिम्मेदार ठहराए गए अधिकारियों एवं ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का न होना भी है। बिहार, दिल्ली, मुम्बई, गुजरात हादसों के दोषियों को बचाने के प्रयास भी सबके सामने हुए हैं। हर हादसे के बाद लीपापोती के प्रयास खूब होते हैं। हादसे में मरने वालों के परिजनों को मुआवजा बांटकर ही अपनी जिम्मेदारी पूरी समझने वाली सरकारों को इससे आगे बढ़ना होगा।

यूरोप राइट तो ब्रिटेन लेफ्ट क्यों?

रहीस सिंह

ब्रिटेन हुए आम चुनाव में ब्रिटिश मतदाताओं ने 14 वर्षों से सत्ता पर काबिज कंजर्वेटिव्स को बेदखल कर कीर स्टार्मर के नेतृत्व में लेबर पार्टी को बड़ी जीत दिलाई। सेंटर-लेफ्ट लेबर पार्टी को ब्रिटेन में मिली यह जीत अन्य यूरोपीय देशों की राजनीतिक धारा के उलट है। इसलिए सवाल उठता है कि ब्रिटेन सेंटर-लेफ्ट के साथ एक नई सुबह लेकर आया है या नई चुनौतियां? अभी जवाब देना मुश्किल होगा। हां, इतना कहा जा सकता है कि ब्रिटेन अन्य यूरोपीय देशों द्वारा खींची गई लकीरों से कुछ अलग चलने का प्रयास कर रहा है। ब्रिटेन के मतदाताओं ने कंजर्वेटिव पार्टी को कुछ थके, अनसुलझे और विवादित रहे चेहरों के कारण सत्ता से बाहर किया या बात कुछ और है? यूरोपीय राजनीति में दक्षिणपंथी उभारों और ब्रिटेन में हुए सत्ता परिवर्तन के बीच के विरोधाभासों को किस तरह से देखा जाए? जिस ब्रिटेन के लोग साढ़े चार साल पहले तक लेबर पार्टी के 'क्रासी नैशनलिस्ट' और 'क्रासी लिबरल' एप्रोच को खारिज कर रहे थे, आज वे 180 डिग्री क्यों घूम गए? चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों ने स्पष्ट कर दिया था कि ऋषि सुनक और उनकी पार्टी बुरी तरह से पराजित होने वाली है। सुनक को ब्रिटेन की जनता ने प्रधानमंत्री नहीं चुना था, वह 'बाई डिफॉल्ट' पीएम बने थे। फिर भी उनसे अपेक्षा की जा रही थी कि वह ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे और वर्ष 2016 से विरोधाभासों से जूझती हुई कंजर्वेटिव पार्टी की साख को दुरुस्त करेंगे। लेकिन, ऐसा हुआ नहीं। सुनक के नेतृत्व में ब्रिटेन 'Get Brexit Done' को ग्लोरिफाई नहीं कर पाया। चुनौतियां अलबत्ता बढ़ती गईं। पिछले सात दशकों के इतिहास में ब्रिटेन में टैक्स की दरें सबसे ज्यादा हो गईं। सरकार के पास लोगों पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, जिसका परिणाम बढ़ते हुए टैक्स के रूप में दिख रहा है। यूक्रेन युद्ध के दौर में जो नीतियां अपनाई गईं, उसके कारण ब्रिटेन में गैस और तेल की कीमतें काफी बढ़ीं। इसका असर आम उपभोक्ता वस्तुओं पर भी पड़ा। सरकार ने एनर्जी संकट से निपटने के लिए उधार लेकर 400 बिलियन पाउंड खर्च कर दिए। बढ़ती महंगाई से निपटने को ब्रिटेन के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें बढ़ा दीं। इससे एक तरफ इकॉनमी क्रैश हुई, दूसरी तरह जनता महंगाई और असुरक्षा के दौर से गुजरी। ऐसे में उसे प्रतिक्रियावादी तो होना ही था। एक बात और, नवंबर 2018 में ब्रिटेन की राजनीति में एक नई पार्टी का प्रवेश हुआ, 'रिफॉर्म यूके'। इसकी और कंजर्वेटिव पार्टी की नीतियां लगभग एक ही जैसी हैं। इसकी बढ़त का सीधा असर कंजर्वेटिव पार्टी पर पड़ा। कीर स्टार्मर पार्टी को एक नए युग में ले जाने के वादे के साथ आगे बढ़े। स्वास्थ्य व्यवस्था, स्टूडेंट्स और टैक्नोक्रेट्स के लिए वेलकम पॉलिसी, रोजगार बढ़ाने के लिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टैक्स क्रिएशन के बजाय वेल्थ क्रिएशन पर फोकस के साथ-साथ यूरोप से रिश्ते सुधारने की उनकी घोषणा ने वहां की जनता पर अच्छा प्रभाव डाला है, लेकिन क्या इससे अपेक्षित परिणाम मिलेंगे? क्या आप्रवासन आने वाले समय में एक नई चुनौती पैदा नहीं करेगा? ब्रेग्जिट का मुख्य कारण था इमिग्रेशन। ब्रिटेन ही नहीं, पूरे यूरोप में इमिग्रेशन का मुद्दा दक्षिणपंथ को बढ़ावा दे रहा है। ऑस्ट्रिया में हंगरी से आने वाली उन ट्रेनों को रोक दिया गया था, जिनमें शरणार्थी आते थे। यही काम डेनमार्क और स्वीडन ने भी किया था। क्या इस तरह का प्रतिरोध सिर्फ इसलिए है कि एक बड़ी आबादी का आव्रजन आर्थिक दबाव और रोजगार की समस्या लेकर आएगा? या यह भय भी काम कर रहा है कि इस विशाल आव्रजन के साथ यूरोप में इस्लामवाद और आतंकवाद का भी आव्रजन हो रहा था? आज जब यूरोप दक्षिणपंथ की तरफ बढ़ रहा है, तब सोचने की जरूरत है कि क्या यूरोपीय समाज में ऐसी विशेषताएं मौजूद हैं, जो इस्लामी कट्टरपंथ और आतंकवाद के लिए रास्ता उपलब्ध करा रही हैं या फिर यह इस्लामोफोबिया का पर्याय है?

काजोल और प्रभुदेवा नजर आएंगे महारागिनी में

बॉलीवुड फिल्म महारागिनी में मशहूर अभिनेत्री काजोल और प्रभुदेवा नजर आने वाले हैं। दोनों कलाकार करीब 27 साल बाद स्क्रीन पर एक साथ नजर आने वाले हैं। इससे पहले ये जोड़ी साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म सपने में नजर आई थी। हाल में ही फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसमें काजोल का दमदार एक्शन देखने को मिला। अभिनेत्री का ये अंदाज देख कर उनके फैंस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। इसी बीच फिल्म को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। इस बहुप्रतीक्षित फिल्म में अभिनेता आदित्य सील भी शामिल हो गए हैं। उन्हें तुम बिन 2 और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी फिल्मों में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। अभिनेता अपनी इस भूमिका को लेकर काफी रोमांचित हैं और उन्होंने इस अवसर को खुद के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा है। एक अभिनेता के तौर पर वह काजोल और प्रभुदेवा का काम देखते हुए बड़े हुए हैं, ऐसे में इन दिग्गजों के साथ पर्दे पर नजर आना, उनके लिए काफी शानदार अनुभव है। वह इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। बीते 28 मई को फिल्म महारागिनी- क्वीन ऑफ क्वींस का टीजर रिलीज हुआ था। इस फिल्म का पहला शेड्यूल पूरा हो चुका है, जिसके बाद ही टीजर जारी किया गया था। इसमें प्रभुदेवा अपने साउथ स्टाइल में काफी जंच रहे थे, जबकि काजोल एक्शन अवतार में मारपीट करती नजर आई थीं। इस दौरान उन्होंने एक दमदार डायलॉग भी बोला, जिसमें वह कहती हैं, पावर मांगकर नहीं, छीन कर ली जाती है। फिल्म में काजोल, प्रभुदेवा, नसीरुद्दीन शाह, आदित्य सील , संयुक्ता मेनन, जीशु सेनगुप्ता जैसे कई शानदार कलाकार नजर आने वाले हैं। महारागिनी फिल्म में दर्शकों को कई रंग देखने को मिलेंगे। इसमें ड्रामा, डांस और इमोशन का एक आकर्षक मिश्रण होने का दावा किया जा रहा है। इसके बारे में बात करते हुए निर्देशक ने कहा है कि उनके लिए इस फिल्म का निर्देशन करना काफी शानदार अनुभव रहा है। उन्होंने फिल्म के कलाकारों के अभिनय की भी तारीफ करते हुए कहा कि उनकी वजह से फिल्म को एक नई ऊंचाई मिली है। वह दर्शकों को इस फिल्म को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि तेलुगु फिल्मों के शानदार निर्देशक चरण तेज उप्पलापति अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म महारागिनी लेकर आने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

रिया के चैप्टर 2 में पहली गेस्ट बनी सुष्मिता सेन

हाल ही में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने अपना नया चैट शो चैप्टर 2 लॉन्च किया है। इस शो की प्रथम गेस्ट बनी हैं पूर्व मिस यूनिवर्स और अभिनेत्री सुष्मिता सेन। हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने इस शो का टीज़र जारी किया है, जिसमें रिया को कुछ ऐसा कहते सुना जा सकता है, जो उनके फैंस के लिए थोड़ा शॉकिंग हो सकता है। रिया चक्रवर्ती ने सुष्मिता सेन के आगे खुद को लेकर एक ऐसी बात कही जो थोड़ा हैरानी भरा था। रिया चक्रवर्ती ने रोडीज में एक गैंग लीडर के तौर पर शोबिज की दुनिया में वापसी की। वहीं, अब वह अपने शो चैप्टर 2 के साथ पॉडकास्टिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसी कड़ी में प्रशंसकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए अभिनेत्री ने पहले एपिसोड की एक दिलचस्प झलक साझा की है। इसमें वह बॉलीवुड डीवा सुष्मिता सेन के साथ नजर आ रही हैं। प्रोमो में दोनों हसीनाओं को गोल्ड डिगर्स के टैग पर चर्चा करते देखा जा रहा है। रिया चक्रवर्ती ने अपने नए शो चैप्टर 2 का प्रोमो जारी किया जिसकी शुरुआत रिया चक्रवर्ती के एक खुलासे से होती है। इसमें वह सुष्मिता सेन के सामने कहती हैं, इस कमरे में आपसे भी बड़ा गोल्ड डिगर है। इस पर सुष्मिता पूछती हैं, सच में तो रिया कहती हैं, हां जी मैं। प्रोमो में रिया को आगे यह भी कहते सुना जाता है कि नफरत चिल्लाकर कही जाती है, लेकिन प्यार महसूस किया जाता है। इसके अलावा सुष्मिता अपने बच्चों की परवरिश पर भी खुलकर बात की। रिया चक्रवर्ती ने कैप्शन में आगे लिखा, इस शो को शुरू करने के लिए सुष्मिता सेन से बेहतर मेहमान कोई नहीं हो सकता। मैं बचपन से ही उन्हें देखती रही हूं और मैं अब भी इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि वह जीवन को कैसे चुनौती देती हैं और उसमें जीत हासिल करती हैं। हमने जीवन, प्रेम और विकास से जुड़ी सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छी बातचीत की। सीक्वल आमतौर पर उबाऊ होते हैं, लेकिन यह नहीं है। स्टे ट्यून्ड चैप्टर 2। मालूम हो कि एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती किसी फिल्म तो नहीं, लेकिन एक नए शो के साथ जरूर दर्शकों के बीच दस्तक दे रही हैं। रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट का नाम चैप्टर 2 है।

कमल हासन ने इंडियन 3 के बारे में बयान देकर माहौल किया गर्म

बालीवुड एक्टर कमल हासन ने इंडियन 3 के बारे में बयान देकर माहौल गर्म कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें दूसरे भाग की तुलना में तीसरा भाग ज्यादा पसंद है। देशभर में इंडियन 2 का प्रचार कर रहे कमल हासन ने पुष्टि की है कि उन्होंने इंडियन 2 सिर्फ़ इसलिए करने के लिए हामी भरी क्योंकि उन्हें इंडियन 3 बहुत पसंद आई थी। सच कहूं तो, मैंने दूसरे भाग को करने के लिए सिर्फ़ इसलिए हामी भरी क्योंकि मैं तीसरे भाग को देखना चाहता था। मैं तीसरे भाग का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। आम तौर पर लोग कहते हैं कि उन्हें फ़िल्म का पहला भाग या दूसरा भाग पहले भाग से ज्यादा पसंद आता है। मेरा दूसरा भाग इंडियन 3 है। मैं खुद फ़िल्म की तारीफ़ करता रहा हूँ और मुझे सिर्फ़ इस बात की चिंता है कि इसके लिए छह महीने का इंतज़ार करना होगा, हसन ने कहा। एक बार फिर शंकर द्वारा निर्देशित, इंडियन 2 में प्रभावशाली स्टार कलाकार हैं। कलाकारों में सिद्धार्थ, एसजे सूर्या, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, प्रिया भवानी शंकर, कालिदास जयराम, गुलशन ग्रोवर, नेदुमुदी वेणु, विवेक, समुथिरकानी, बॉबी सिम्हा, गुरु सोमसुंदरम, दिल्ली गणेश, जयप्रकाश, मनोबाला, वेनेला किशोर और दीपा शामिल हैं। शंकर सहित अन्य लोग शामिल थे। अनिरुद्ध रविचंदर ने फिल्म के दोनों भागों के लिए संगीत तैयार किया है। मेकर्स ने दोनों पार्ट की शूटिंग पूरी कर ली है। इंडियन 2 के ऑडियो लॉन्च पर बोलते हुए, शंकर ने खुलासा किया कि उन्होंने तीसरा पार्ट इसलिए बनाया क्योंकि एक पार्ट उनके कंटेंट की आत्मा के साथ न्याय नहीं कर रहा था। इंडियन 2, इंडियन (1996) के बाद की कहानी है, जिसमें कमल हासन ने पिता और पुत्र की दोहरी भूमिका निभाई थी। हासन का किरदार सेनापति एक पूर्व स्वतंत्रता सेनानी है जो भ्रष्ट अधिकारियों का पता लगाकर आधुनिक समाज में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जब उसके बेटे के भ्रष्ट इंस्पेक्टर होने का पता चलता है, तो सेनापति उसे भी नहीं छोड़ता। बता दें कि इंडियन- 2 12 जुलाई को सिनेमाघरों में आने वाली है। इंडियन-2 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है।

आलिम ने अर्जुन को दिया सदा सेक्सी रहो का आशीर्वाद

हाल ही में सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर के बालों को हाइलाइट कर मेकओवर किया और उनका एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो में अर्जुन सैलून की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं और अपने नए हेयर स्टाइल को दिखा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए आलिम ने कैप्शन में लिखा, खुशियों को हाइलाइट करें। अपने बालों को स्टाइल करना हमेशा मजेदार होता है... इस पोस्ट पर अर्जुन ने कमेंट में लिखा, आपका आशीर्वाद, जिस पर रिप्लाई देते हुए आलिम ने लिखा, सदा सेक्सी रहो। बड़े पर्दे की बात करें तो अर्जुन फिल्म मेकर रोहित शेट्टी की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन में नजर आएंगे। इस फिल्म में वह विलेन के रोल में दिखाई देंगे। सिंघम अगेन में अजय देवगन, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर खान और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार भी हैं। हेयरस्टाइलिस्ट की बात करें तो हाल ही में आलिम ने क्रिकेटर युवराज सिंह और एमएस धोनी के लिए हेयर स्टाइलिंग करते हुए वीडियो भी शेयर किए। युवराज का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, वन एंड ओनली युवराज सिंह। धोनी के लिए उन्होंने कैप्शन दिया, हमारे यंग, डायनामिक और हैंडसम महेंद्र सिंह धोनी। उन्होंने सुपरस्टार रजनीकांत की एक तस्वीर भी शेयर की और लिखा, किंग के साथ उनका दिन बहुत बढ़िया रहा। बता दें कि बॉलीवुड में आलिम हकीम सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पर काफी पॉपुलर हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान, एमएस धोनी से लेकर विराट कोहली तक, हर कोई उनके हेयर कटिंग को पसंद करता है।

चाणक्य बंद नहीं हुई है यह बनेगी जरूरः नीरज पांडे

बालीवुड अक्षय कुमार के साथ फिल्में बनाने वाले निर्देशक नीरज पांडे ने भी एक बार अजय देवगन को लेकर बड़े स्तर पर चाणक्य नामक फिल्म बनाने का ऐलान किया था, लेकिन यह फिल्म बन नहीं पाई।
कहा गया कि यह फिल्म अब कभी नहीं बनेगी इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लेकिन हाल ही में नीरज पांडे ने इस बात की पुष्टि की है कि फिल्म बंद नहीं हुई है यह बनेगी जरूर, पर फिलहाल इसे होल्ड पर रखा गया है। गौरतलब है कि अजय देवगन को लेकर चाणक्य बनाने वाले निर्देशक नीरज पांडे ने चाणक्य को होल्ड करके अजय देवगन के साथ औरों में कहाँ दम था का निर्माण व निर्देशन किया है। फिल्म आगामी शुक्रवार 5 जुलाई को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने जा रही है। नीरज ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपनी फिल्मों को लेकर कई बातें शेयर कीं। जब नीरज से उनकी फिल्म 'चाणक्य' के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कई कारणों से वह फिल्म नहीं बन पाई है। फिलहाल हमने उसे होल्ड पर डाल दिया है। मुझे लगता है कि काफी समय से हममें एक गिल्ट सा था कि एक प्रोजेक्ट में हमने अपना काफी समय दे दिया है और वह प्रोजेक्ट बन नहीं पाया। फिर मैंने यह फिल्म बना ली। इस फिल्म के लिए वहीं से बातचीत शुरू हुई थी। मेरे पास यह कहानी थी। कलाकारों को सुनाई और फिल्म शुरू हो गई। यह कहानी कोलकाता में मेरे बड़े होने के दौरान का एक अहम हिस्सा रही है। इस कहानी का एक हद तक श्रेय मैं अपनी जन्मस्थली को दूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा कि वह घटना कभी कहानी में परिवर्तित होगी या एक दिन उस पर स्क्रिप्ट लिखूंगा। घटना के बारे में नहीं बता सकता वरना फिल्म का मजा खराब हो जाएगा। बता दें कि अजय देवगन को फिल्म उद्योग में आए 34 साल हो चुके हैं। इन 34 सालों में उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों को दर्शकों के सामने पेश किया है। उनका अपना एक अलग दर्शक वर्ग है जो लगातार उनकी फिल्मों को देखना पसन्द करता है। फिल्म उद्योग का हर बड़ा निर्माता निर्देशक अजय देवगन के साथ काम करना चाहता है।

अरबाज के शो में बतौर स्पेशल गेस्ट शामिल हुई शबाना

स्ट्रीमिंग चैट शो द इनविन्सिबल्स विद अरबाज खान में एक्ट्रेस शबाना आजमी ने खुलासा किया कि एक्टर मिथुन चक्रवर्ती इंडस्ट्री में शुरुआती दिनों में अपने स्किन टोन को लेकर काफी चिंता में रहते थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अरबाज खान के स्ट्रीमिंग चैट शो द इनविन्सिबल्स विद अरबाज खान में अनुभवी एक्ट्रेस शबाना आजमी स्पेशल गेस्ट के तौर पर शामिल हुईं। शो के होस्ट अरबाज खान से बात करते हुए शबाना ने बताया कि मिथुन चक्रवर्ती, जो उस समय मेरे जूनियर थे, हमारे घर आते थे और हमें बताते थे कि उनका रंग गोरा नहीं है या उनके दांत अलग हैं। मां उन्हें गले लगाती और कहती थीं, तुम्हें इन सब चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम बहुत अच्छे डांसर हो... मां की ये बातें सुनकर, हम सभी को एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता था। अपनी हिट फिल्म अर्थ के बारे में शबाना ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में शामिल किसी भी कलाकार ने इतने सालों में इसके कल्ट स्टेटस की उम्मीद नहीं की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड मिला। एक्ट्रेस ने कहा कि इस फिल्म ने समाज में बदलाव की शुरुआत की। अर्थ 1982 में रिलीज हुई थी। इसमें शबाना आजमी के अलावा, कुलभूषण खरबंदा और स्मिता पाटिल अहम भूमिका में थे। एपिसोड के दौरान उन्होंने अपने पति व लेखक जावेद अख्तर की शराब की लत से डील कैसे किया, इस बारे में भी बात की। एक्ट्रेस ने कहा- एक दिन जब वे पेरिस में थे, तो जावेद शराब के नशे में थे और उसी पल उन्होंने शराब छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने पति की इच्छाशक्ति की सराहना की और कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक उन्होंने शराब कैसे छोड़ दी। बता दें कि एक्ट्रेस ने हाल ही में सिनेमा में 50 साल पूरे किए। शबाना आजमी और मिथुन चक्रवर्ती ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है, इनमें समीरा, हम पांच, झूठी शान, नसीहत, अशांति और अमर दीप शामिल हैं।

भारतीय फिल्म महोत्सव में गर्ल्स विल... ने दर्ज की बडी जीत

फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने लॉस एंजिल्स के भारतीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफएलए) में ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा और अली फजल द्वारा समर्थित इस फिल्म ने पहले ही कई पुरस्कार जीत लिए थे। शुचि तलाटी द्वारा निर्देशित फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने पहले रोमानिया में ट्रांसिल्वेनिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और फ्रांस में बियारिट्ज़ फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीते थे। इसने सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में दो प्रमुख पुरस्कार भी जीते। इस आने वाली उम्र की ड्रामा में कनी कुसरुति और प्रीति पाणिग्रही मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की अनूठी कथा और सम्मोहक अभिनय ने कई पुरस्कार जीते हैं, जो इसके निर्माण के पीछे की प्रतिभा और दृष्टि को दर्शाता है। आईएफएफएलए में अपनी फिल्म की बड़ी जीत पर अपनी खुशी साझा करते हुए, होने वाली मां ऋचा चड्ढा ने कहा, आईएफएफएलए में ग्रैंड ज्यूरी पुरस्कार जीतना एक अविश्वसनीय सम्मान है। हमारी पूरी टीम की कड़ी मेहनत और समर्पण को ऐसे प्रतिष्ठित मंच पर मान्यता मिलना बहुत संतोषजनक है। गर्ल्स विल बी गर्ल्स एक ऐसी कहानी है जो हमारे दिल के करीब है और हम रोमांचित हैं कि यह दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आ रही है। उन्होंने कहा, यह इस महीने फिल्म की तीसरी जीत है, जो बहुत बड़ी बात है। प्रतिक्रिया जबरदस्त रही है और फिल्म को जो प्यार मिल रहा है वह वाकई असाधारण है। हम निर्माता के तौर पर इससे बेहतर शुरुआत पाकर बहुत खुश हैं।
अली फजल ने कहा, यह यात्रा किसी जादुई अनुभव से कम नहीं है। सनबर्न से लेकर कान्स और अब आईएफएफएलए तक, प्रत्येक पुरस्कार प्रामाणिक कहानी कहने की शक्ति में हमारे विश्वास की पुष्टि करता है। हमें मिले समर्थन और प्यार के लिए हम आभारी हैं, और हम यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि गर्ल्स विल बी गर्ल्स आगे कहाँ तक जाती है। इंडो-फ्रेंच सह-निर्माण में बनी गर्ल्स विल बी गर्ल्स 16 वर्षीय मीरा (जिसे प्रीति पाणिग्रही ने निभाया है) और उसकी माँ के साथ उसके तनावपूर्ण संबंधों के बारे में एक आने वाली उम्र का नाटक है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

8 जुलाई को मणिपुर जा सकते हैं राहुल गांधी

नईदिल्ली। मणिपुर संकट से निपटने और समाधान के लिए विपक्षी नेता राहुल गांधी ने 8 जुलाई को मणिपुर का दौरा करने का कार्यक्रम बनाया है। अपनी यात्रा के दौरान, गांधी राज्य के सीएसओ नेताओं से मिलेंगे और चुराचांदपुर, मोइरांग और अन्य स्थानों में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से मिलेंगे। राहुल गांधी की मणिपुर की निर्धारित यात्रा विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त होने के बाद देश भर में उनकी पहली यात्रा होगी। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर अपनी नीतियों और राजनीति के कारण मणिपुर को गृहयुद्ध में धकेलने का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता ने जातीय हिंसा भड़कने के बाद से राज्य का दौरा नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में विपक्ष की ओर से बहस की शुरुआत करते हुए गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे मणिपुर में कुछ हुआ ही नहीं है।

नए सिरे से कराई जाए नीट यूजी परीक्षा : खरगे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। इस मामले में केंद्र सरकार के हलफनामे को लेकर खरगे ने शनिवार को कहा कि लाखों युवाओं से सफेद झूठ बोला जा रहा है और उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। दरअसल विवादों में घिरी नीट-यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने की मांग बढ़ती जा रही है। इसके बीच, केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में दिए हलफनामे में कहा कि इसे रद्द करना बेहद प्रतिकूल होगा और व्यापक जनहित के लिए, विशेष रूप से इसे उत्तीर्ण करने वालों के करियर को नुकसान हो सकता है। मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा पोस्ट में लिखा, मोदी सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय को बताया है कि नीट-यूजी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है! लाखों युवाओं से ये सफेद झूठ बोला जा रहा है।

ओडिशा विधानसभा का पहला सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा

भुवनेश्वर। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के अभिभाषण के साथ 17वीं ओडिशा विधानसभा का पहला सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और यह 13 सितंबर तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से शुक्रवार को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में 22 जुलाई को चर्चा शुरू होगी और 24 जुलाई को समाप्त होगी। ओडिशा विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव भी 24 जुलाई को होगा। अधिसूचना के अनुसार, वित्त विभाग का भी प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 25 जुलाई को वर्ष 2024-25 के लिए राज्य की भाजपा सरकार का पहला वार्षिक बजट पेश करेंगे। ओडिशा की 147 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 78, बीजू जनता दल (बीजद) के 51 और कांग्रेस के 14 सदस्य हैं। इसके अलावा, तीन निर्दलीय और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) का एक विधायक है।

महाविकास अघाड़ी में टूट के संकेत?

मुंबई। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शायद सबकुछ ठीक नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के ताजा बयान से ऐसे संकेत मिले हैं कि गठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं है। दरअसल नाना पटोले ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी, लेकिन चुनाव अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे के समझौते के अनुसार लड़ेगी। नागपुर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए पटोले ने कहा कि अगर पार्टी सभी सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी करती है तो यह गलत नहीं है, क्योंकि पार्टी के पास अपना संगठनात्मक ढांचा होना चाहिए और कार्यकर्ताओं को हर जगह काम करना चाहिए। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव इस साल अक्टूबर में होने हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक पार्टी के पास हर जगह अपना संगठनात्मक ढांचा और काम होना चाहिए। सीटों के बंटवारे के आधार पर गठबंधन बनाया जाएगा।

क्रिकेटरों को 11 करोड़ रुपये इनाम देने पर विपक्ष बिफरा

मुंबई। महाराष्ट्र में विपक्षी कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) ने एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम को 11 करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि ऐसा करके सरकार अपनी पीठ थपथपाना चाहती है। विपक्षी दलों ने कहा कि उन्हें क्रिकेटरों की उपलब्धि पर गर्व है, लेकिन राज्य के खजाने से 11 करोड़ रुपये देने की कोई जरूरत नहीं है और उन्होंने मुख्यमंत्री से अपनी जेब से यह राशि देने को कहा। हालांकि, भाजपा ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 11 करोड़ रुपये के नकद इनाम की घोषणा की। यह घोषणा विधान भवन (राज्य विधानमंडल परिसर) में की गई, जहां टीम के चार मुंबई खिलाड़ियों - कप्तान रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे को सम्मानित किया गया।

जैसे हमारा कार्यालय तोड़ा, वैसे हम उनकी सरकार तोड़ेंगे : राहुल

■ राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

अहमदाबाद। लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी फिलहाल गुजरात दौरे पर हैं। शनिवार यानी की आज वह अहमदाबाद पहुंचे। राहुल आज राजकोट गेम जोन अग्निकांड के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वह अहमदाबाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। राहुल गांधी के अहमदाबाद दौरे पर बजरंग दल विरोध प्रदर्शन कर रहा है। वे कांग्रेस सांसद के लोकसभा में हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान से नाराज हैं।

अहमदाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ में उन्होंने गुजरात में कांग्रेस की खामियों पर भी बात की। कांग्रेस सांसद ने कहा, जिस तरह से उन्होंने हमारा कार्यालय तोड़ा, उसी तरह हम उनकी सरकार तोड़ने जा रहे हैं। गुजरात कांग्रेस में कमियां है। यहां दो तरह के घोड़े हैं। एक का इस्तेमाल दौड़ के लिए और दूसरे का इस्तेमाल शादी के लिए किया जाता है। कांग्रेस रेस के घोड़े को शादी में और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। पिछले चुनावों में हमनें भाजपा के खिलाफ ठीक से चुनाव नहीं लड़ा। 2017 में हमने तीन महीनों के लिए काम किया थी जिसका परिणाम अच्छे आए थे। अब हमारे पास तीन साल है। हम फिनिशिंग लाइन को पीछे छोड़ देंगे। आप 30 साल बाद गुजरात में जीतने वाले हैं। मैं और मेरी बहन आपके साथ खड़े हैं।

उन्होंने कहा, भाजपा की पूरी मूवमेंट राम मंदिर, अयोध्या की थी। शुरुआत आडवाणी जी ने की थी, रथयात्रा की थी। कहा जाता है नरेंद्र मोदी जी ने उस रथयात्रा में आडवाणी जी की मदद की थी। मैं संसद में सोच रहा था कि उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और प्राण प्रतिष्ठा में अडानी-अंबानी जी दिख गए लेकिन गरीब व्यक्ति नहीं दिखा। संसद में मैंने अयोध्या के सांसद से पूछा कि, ये भाजपा ने अपनी पूरी राजनीति चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। लेकिन इंडी गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया, यह क्या हुआ? राहुल गांधी ने आगे कहा, अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा राहुल जी मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से चुनाव लड़ने वाला हूं और जीतने भी वाला हूं। उन्होंने कहा, मुझे अयोध्या के लोग कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए हमारी जमीन ली गई, कई दुकानें-घर तोड़े गए और सरकार ने आज तक लोगों को मुआवजा नहीं दिया। अयोध्या का बड़ा एयरपोर्ट बना उसमें अयोध्या के किसानों की जमीन गई, जिसमें किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्यावासी ही नहीं थे। इससे पहले राहुल गांधी के दौरे का विवरण देते हुए शक्तिसिंह गोहिल ने कहा, हमारे नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी छह जुलाई को अहमदाबाद में राज्य कांग्रेस कार्यालय आ रहे हैं। वह कांग्रेस परिवार के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने आगे कहा, मुझे पूरे गुजरात से कई लोगों ने फोन किया, जिनके साथ भाजपा ने अन्याय किया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी न्याय के लिए लड़ते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें भाजपा पर भरोसा था, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। अब वे राहुल गांधी के सामने अपनी बार रखना चाहते हैं। इसलिए हम भी उनसे अनुरोध करते हैं कि वे एक बार बात करें। राहुल गांधी शनिवार को 12 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे।

अग्निवीर को लेकर राहुल ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बार फिर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए अग्निवीर अजय कुमार के परिवार के दावों पर सवाल उठाया और कहा कि उन्हें सरकार से अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। रायबरेली के सांसद ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया जिसमें मृतक अग्निवीर के पिता को यह कहते हुए दिखाया गया कि उनके परिवार को एक निजी बैंक से बीमा के रूप में 50 लाख रुपये और आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से 48 लाख रुपये मिले।

विपक्ष के जाति जनगणना की रणनीति को लगा जोर का झटका!

प्रधानमंत्री के साथ मिलकर चंद्रबाबू नायडू ने बनाया मास्टरप्लान

नईदिल्ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू राज्य में कौशल जनगणना शुरू कर रहे हैं और जनसंख्या के पास उपलब्ध कौशल सेटों को मैप करने और मानव पूंजी विकसित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को एक समान अभ्यास का सुझाव देंगे। जाति जनगणना पर जोर देने वाले इंडिया ब्लॉक राज्यों के विपरीत, नायडू ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य नागरिकों के लिए बेहतर परिणाम उत्पन्न करने के लिए पीपीपी को सार्वजनिक, निजी, लोगों की भागीदारी में विस्तारित करना है। केंद्रीय बजट में अपेक्षित कुछ उपायों के साथ कौशल और रोजगार सृजन को मोदी सरकार के लिए मुख्य फोकस के रूप में देखा जाता है।

राजधानी में कई बैठकों के बाद, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रमुख सहयोगी टीडीपी प्रमुख ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी सरकार द्वारा राज्य को गंभीर वित्तीय तनाव में छोड़ने के बाद आंध्र प्रदेश का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। नायडू का इरादा पांच श्वेत पत्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से तनाव और विकास की अनुपस्थिति को उजागर करने का है, जिसके कारण पोलावरन सिंचाई परियोजना और अमरावती को नई राज्य राजधानी बनाने की उनकी योजना में व्यवधान देखा गया है।

नायडू ने कहा कि वह लोगों को तय करने देंगे कि क्या करना है। वह आंध्र को विकास पथ पर वापस लाने और घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपने पहले के अनुभव का उपयोग करने पर भी विचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा, आंध्र के मुख्यमंत्री ने कई उद्योग जगत के नेताओं से भी मुलाकात की और स्वीकार किया कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की स्थिति में राजनीतिक माहौल को लेकर चिंताएं थीं। नायडू ने कहा, वे शैतान को लेकर चिंतित हैं। हम उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि हम इसे नियंत्रित करेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी पार्टी किसी सीट या साझा एजेंडे की मांग नहीं कर रही है क्योंकि भाजपा और गठबंधन सहयोगियों ने अपने-अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं।

उन्होंने कहा, हमने केंद्र से कोई मंत्री पद नहीं मांगा, यहां तक कि वाजपेयी के समय में भी नहीं। जो भी पेशकश की गई, हमने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की प्राथमिकता आंध्र प्रदेश का पुनर्निर्माण है, जिसे पिछले पांच वर्षों में अपूरणीय क्षति हुई है। हमारा लक्ष्य अगले पांच वर्षों में राज्य का पुनर्निर्माण करना है। आंध्र प्रदेश के लोगों ने एनडीए को जनादेश दिया है। हम मिलकर काम करेंगे। अल्पसंख्यकों के लिए कोटा पर, एक मुद्दा जिसे मोदी ने आम चुनावों के दौरान चिंता के रूप में उठाया था, नायडू ने कहा कि उनकी पार्टी ने आरक्षण देने के लिए आर्थिक पिछड़ेपन का इस्तेमाल किया था, अन्य कारणों का नहीं।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हर भारतीय है ऋणी : अमित शाह

■ बोले- राष्ट्र प्रथम के पथ पर सदैव मार्गदर्शक रहेंगे

नईदिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मंत्री ने कहा कि प्रत्येक भारतीय देश की अखंडता के लिए उनके अद्वितीय प्रयासों के लिए मुखर्जी का ऋणी है। शाह ने कहा कि मैं प्रख्यात राष्ट्रवादी विचारक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर याद करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जब भी देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ने की बात होगी, डॉ. मुखर्जी को जरूर याद किया जाएगा। चाहे वह बंगाल को देश का हिस्सा बनाए रखने के लिए उनका संघर्ष हो या %एक निशान, एक प्रधान, एक विधान% के संकल्प के साथ जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान देना, हर भारतीय उनका ऋणी है। देश की अखंडता के लिए उनके अनूठे प्रयास। जनसंघ की स्थापना कर देश को एक वैचारिक विकल्प प्रदान करने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्र प्रथम के पथ पर सदैव मार्गदर्शक रहेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भाजपा विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 123वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मोदी ने कहा कि मुखर्जी ने अपने उग्र राष्ट्रवादी विचारों से भारत को गौरवान्वित किया और मातृभूमि के प्रति उनका बलिदान और समर्पण लोगों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। वह जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के सदस्य थे, जिसे उन्होंने प्रधान मंत्री के साथ अपने मतभेदों के विरोध में छोड़ दिया और फिर आरएसएस के समर्थन से जनसंघ का गठन किया। मुखर्जी की 1953 में जम्मू-कश्मीर में उन भारतीय नागरिकों पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के बाद मृत्यु हो गई, जो राज्य से नहीं थे। वे राज्य को दिये गये विशेष दर्जे के विरोधी थे।

खेल
प्रमुख समाचार

प्रज्ञाननंदा और गुकेश टाईब्रेकर में हारे, कारुआना ने जीता खिताब

बुखारेस्ट। भारत के आर प्रज्ञाननंदा और डी गुकेश को चार खिलाड़ियों के बीच खेले गए टाइब्रेकर में हार का सामना करना पड़ा जिसमें दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी फैबियानो कारुआना ने तीनों रैपिड गेम जीतकर सुपरबेट क्लासिक में अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। कारुआना क्लासिकल प्रारूप में नीदरलैंड के अनीश गिरी से हार गए, जिससे मुकाबला रोचक बन गया क्योंकि गुकेश, प्रज्ञाननंदा और फ्रांस के अलीरेजा फिरौजा सभी उनकी बराबरी पर पहुंच गए।

प्रज्ञाननंदा मुख्य बाजी में अलीरेजा के सामने एक समय बेहद मुश्किल स्थिति में फंसे हुए थे। यदि फ्रांसीसी खिलाड़ी क्लासिकल दौर की इस बाजी को जीत जाता तो फिर वह कारुआना से आगे निकल जाते और विजेता का फैसला करने के लिए टाइब्रेकर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कारुआना हार गए, जबकि गुकेश और प्रज्ञाननंदा ने अपनी अपनी बाजियां ड्रॉ खेली जिससे विजेता का फैसला करने के लिए चार खिलाड़ियों के बीच टाइब्रेकर की स्थिति बन गई। कारुआना ने दिखाया कि आखिर उन्हें क्यों टाइब्रेकर का मास्टर कहा जाता है।

उन्होंने साबित कर दिया कि वे युवा पीढ़ी से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अमेरिका के इस खिलाड़ी ने टाइब्रेकर में अपने तीनों प्रतिद्वंदियों गुकेश, प्रज्ञाननंदा और अलीरेजा को हराकर 68500 अमेरिकी डॉलर का पहला पुरस्कार जीता। इससे पहले प्रज्ञाननंदा टूर्नामेंट में अपनी पहली हार की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन अलीरेजा की एक गलती का फायदा उठाकर वह बाजी ड्रा करने में सफल रहे। गुकेश ने वेस्ली सो के साथ अंक बांटकर टाइब्रेकर में खेलने का हक पाया था।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

भारत ऑर्गेनिक्स के आटे की लॉन्चिंग

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सहकारिता के 102वें अंतरराष्ट्रीय दिवस पर आयोजित सहकार से समृद्धि तक कार्यक्रम में भाग लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सहकारिता के 102वें अंतरराष्ट्रीय दिवस को संबोधित किया। इस दौरान भारत ऑर्गेनिक्स की ओर से तैयार गेहूं के आटे और दिल्ली के मयूर विहार में अमूल ऑर्गेनिक्स स्टोर की लॉन्चिंग की गई।

बजट से पहले स्टार्टअप से एंजल कर हटाने की सिफारिश

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के अंशकालिक सदस्य नीलेश शाह ने कहा कि सट्टा कारोबार पर अंकुश लगाने और लंबे समय के लिए निवेश की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। लंबे समय में पूंजी निवेश खुदरा निवेशकों और भारतीय कंपनियों के लिए धन सृजन कर सकता है। एक कार्यक्रम में नीलेश शाह ने कहा, सट्टा कारोबार को हतोत्साहित करना चाहिए, ताकि निवेश को बढ़ावा मिले। लोग पैसा खो देते हैं। यदि सरकार फ्यूचर और ऑप्शन या सट्टा कारोबार के लिए उच्च कराधान पर विचार करे तो यह सही कदम होगा। उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी डीपीआईआईटी ने बजट से पहले स्टार्टअप कंपनियों पर से एंजल कर हटाने की सिफारिश की है।

आरबीआई ने पांच बैंकों पर की कार्रवाई

नई दिल्ली। जुलाई के पहले सप्ताह में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और चार अन्य बैंकों पर आरबीआई के विभिन्न निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया। पीएनबी पर 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावे गुजरात राज्य कर्मचारी सहकारी बैंक, गुजरात; रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, मधुबनी, बिहार; राष्ट्रीय सहकारी बैंक, मुंबई, महाराष्ट्र; और बैंक कर्मचारी सहकारी बैंक, पश्चिम बंगाल चार अन्य बैंक हैं जिन पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया था।

मकानों की बिक्री में आया भारी उछाल

नईदिल्ली। अर्थव्यवस्था में तेजी और कोरोना के बाद बढ़ती मांग से मकानों की बिक्री में भारी उछाल आया है। इससे पिछले 10 वर्षों में 23 राज्यों ने संपत्तियों के पंजीकरण के एवज में 13.7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की स्टांप ड्यूटी वसूली है। बैंक ऑफ बड़ौदा की शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2015 से 2019 के बीच 23 राज्यों में स्टांप शुल्क की वार्षिक चक्रवृद्धि दर 10.4 फीसदी रही है। महामारी के बाद वित्त वर्ष 2019 से 2024 के बीच यह दर 12.5 फीसदी रही है। इससे संकेत मिलता है कि कोरोना के बाद मकानों की बिक्री में अच्छा उछाल आया है। 23 राज्यों में से 16 राज्यों में स्टांप ड्यूटी बढ़ी है। 10 वर्षों में स्टांप शुल्क दर में काफी बदलाव आया है। कोरोना के समय कुछ राज्यों ने शुल्क को शून्य कर दिया था। हालांकि, अब यह कोरोना के पहले के स्तर पर वापस आ गया है।

कठिन आर्थिक दौर से ब्रिटेन को बाहर निकालने का श्रेय ऋषि सुनक को ही जायेगा

नीरज कुमार दुबे

ब्रिटेन की जनता ने इस बार के आम चुनाव में सत्ता पलट दी है। महंगाई की सर्वाधिक मार झेलने वाली ब्रिटेन की जनता ने कंजरवेटिव पार्टी को चुनावों में कड़ा सबक सिखाया है जिसके चलते प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को माफी मांगते हुए यह कहना पड़ा है कि मैंने आपके गुस्से और निराशा को महसूस किया है और मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं। वैसे चुनाव के नतीजे जो भी रहे हों लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ऋषि सुनक ने अपने देश को कठिन आर्थिक परिस्थितियों के दौर से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद जब लिज ट्रस ने ब्रिटेन की कमान संभाली थी तो तुरंत ही उन्हें अर्थव्यवस्था की बिगड़ी सेहत का अंदाजा हो गया था और उन्होंने महज 45 दिनों के भीतर ही प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था। उस समय ऋषि सुनक ही अंतिम तारणहार दिखाई पड़ रहे थे। देखा जाये तो ऋषि सुनक ने उस समय प्रधानमंत्री के रूप में कांटों का ताज पहना था क्योंकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था महामारी के बाद हिचकोले खा रही थी। महंगाई और ब्याज दरें बढ़ रही थीं। यूक्रेन युद्ध ने ऊर्जा पर होने वाले खर्च को बढ़ा दिया था। मुद्रा बाजार में स्टर्लिंग (ब्रिटेन में प्रचलित मुद्रा) कमजोर दिख रही थी। एक सफल बैंकर और वित्त मंत्री रहे सुनक ने प्रधानमंत्री बनते ही बजट घाटे को काबू में किया, सरकार के खर्चों में कटौती की और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आये लेकिन वैश्विक संघर्षों के चलते बाधित हुई सप्लाई चेन की वजह से बढ़ती महंगाई को वह नहीं रोक पाये। इसके अलावा चूंकि उनकी पार्टी पिछले लगभग डेढ़ दशक से सत्ता में थी इसलिए ब्रिटेन में इस बार बदलाव की जोरदार लहर चल रही थी जोकि परिणामों में स्पष्ट नजर आ रही है।

वैसे ब्रिटेन के आम चुनावों में बदलाव होने वाला है इसके संकेत पिछले साल हुए उपचुनावों में ही मिल गये थे। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद से ऋषि सुनक की वैश्विक लोकप्रियता में तो इजाफा हुआ था लेकिन ब्रिटेन में पिछले साल तीन सीटों पर हुए उपचुनाव में उनकी कंजरवेटिव पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। अब आम चुनावों में कंजरवेटिव पार्टी को अपने इतिहास की सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ है कि क्या सुनक की नीतियां जनता को पसंद नहीं आ रही थीं? सवाल यह भी उठा है कि कंजरवेटिव पार्टी को गलत नीतियों की सजा चुनावों में मिली या पार्टी को एकजुट नहीं होने का खामियाजा भुगतना पड़ा है? सवाल यह भी है कि क्यों कंजरवेटिव पार्टी के नेता और सांसद ही अक्सर विवादों में रह कर सुनक की मुश्किलें बढ़ा रहे थे?

इसके अलावा, 14 वर्षों से ब्रिटेन की सत्ता में रही कंजर्वेटिव पार्टी की हालत चुनावों से पहले ही खस्ता नजर आ रही थी क्योंकि कई लोगों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और पार्टी के कई नेता और सलाहकार नई नौकरियों की तलाश में निकल पड़े थे। अब कंजर्वेटिव पार्टी के जो लोग जीत कर आये हैं वह प्रभावी विपक्ष की भूमिका सही से निभा पाएंगे, इसके बारे में विश्लेषकों को संदेह है। माना जा रहा है कि लेबर पार्टी को कुछ वर्षों तक खुली छूट मिली रहेगी।

जहां तक चुनाव परिणाम की बात है तो आपको बता दें कि ऋषि सुनक तो चुनाव जीत गये लेकिन उनके मंत्रिमंडल में शामिल पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस और कई कैबिनेट मंत्री पराजित हो गए। सुनक उत्तरी इंग्लैंड में अपनी रिचमंड एवं नॉर्थलेरटन सीट पर 23,059 वोट के अंतर के साथ दोबारा जीत हासिल करने में सफल रहे हैं। लेकिन रक्षा मंत्री ग्रांट शेप्स, न्याय मंत्री एलेक्स चाक और मिशेल डोनेलन जैसे बड़े नेता चुनाव हार गये। ब्रिटेन के आम चुनाव में लेबर पार्टी के बहुमत से काफी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करते ही ऋषि सुनक ने हार स्वीकार कर ली और लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर को बधाई दी। उन्होंने किंग चार्ल्स से मिलकर अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया।

विद्यार्थियों की उपलब्धियां, कठिन परिश्रम, समर्पण, शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रमाणः राज्यपाल

पं. सुंदरलाल शर्मा मुक्त विवि के छठवें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री

शिक्षा का मूल उद्देश्य ''सर्वे भवंतु सुखिनः'' के ध्येय वाक्य के साथ एक दूसरे की मदद करनाः मुख्यमंत्री

रायपुर। राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर के छठवें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में विभिन्न शैक्षणिक सत्रों की परीक्षाओं में छात्रों को स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, पत्रोपाधि के लिए उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। इस मौके पर श्री राम प्रताप सिंह एवं सुश्री सुरभा देश पांडे को विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि दी गई। समारोह में कुलाधिपति द्वारा पीएचडी छात्रों को उपाधि प्रदान की गई एवं इस उपाधि के आचार एवं गौरव की रक्षा करने का संदेश दिया गया। अतिथियों ने उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने समारोह में अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए कहा कि मुझे छठवें दीक्षांत समारोह में शामिल होते हुए बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने स्वर्ण पदक एवं उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और उपाधि प्राप्त करने वाले शोधार्थियों के परिवारजनों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि उनके सहयोग, त्याग एवं मार्गदर्शन में आपने ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्यपाल हरिचंदन ने छात्रों से कहा कि आपकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां आपके कठिन परिश्रम, समर्पण, आपकी शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय 21 मार्च 2005 को स्थापित हुआ। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ में जन जागरूकता एवं सामाजिक प्रगति लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह विश्वविद्यालय पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के सपनों को गढ़ने एवं साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने उच्च शिक्षण गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय को नैक द्वारा ए प्लस ग्रेड दिए जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

राज्यपाल हरिचंदन ने कहा कि विकसित भारत, समृद्ध भारत की संकल्पना पर आधारित है। विकसित भारत संकल्पना के जरिए क्षेत्र के सभी नागरिकों को अपनी क्षमता के अनुसार विकास करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय जनजाति क्षेत्र में रहने वाले अति पिछड़े समुदायों तथा कॉविड-19 से प्रभावित लोगों को शिक्षा का अवसर प्रदान कर अपने सामाजिक सरोकारों के उद्देश्य को भी पूरा कर रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक एवं उपाधि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। श्री साय ने कहा मुझे प्रसन्नता है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र यह मुक्त विश्वविद्यालय अपने अकादमिक और शैक्षणिक गतिविधियों के साथ नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। दूरस्थ अंचलों में बसे ऐसे शिक्षार्थियों के लिए जो किसी कारणवश उच्च शिक्षा से वंचित रह गए हैं या नौकरी पेशा वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जो अपने भावी सपनों को साकार करना चाहते हैं, उनके लिए यह विश्वविद्यालय शिक्षा के अवसर प्रदान करने का प्रमुख केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मैं स्वयं राज्य के दूरस्थ क्षेत्र जशपुर का हूं इसलिए मैंने हमारे छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों के लोगों की कठिनाईयों को बहुत नजदीक से देखा है मैं दूरस्थ अंचलों में बसे हमारे राज्य के लोगों की कठिनाईयों को महसूस कर सकता हूं। मुझे खुशी है कि विश्वविद्यालय अपने ध्येय वाक्य ''उच्च शिक्षा आपके द्वार'' के अनुरूप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा, शिक्षा का मूल उद्देश्य सर्वे भवंतु सुखिन: के ध्येय वाक्य के साथ एक दूसरे की मदद करना है। हमारे राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किए जाने से युवाओं में तार्किक क्षमता के संवर्धन के साथ ही उनका सर्वांगीण विकास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय को यूजीसी के 235 विश्वविद्यालयों की उस सूची में शामिल किया गया है, जो संयुक्त अथवा दोहरी डिग्री दे सकता है। अब यह विश्वविद्यालय विदेशी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर संयुक्त डिग्री के लिए कार्यक्रम शुरू कर सकता है, यह खुशी की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालय से जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिवार की प्रशंसा करते हुए कहा मेरा सुझाव है कि विश्व के लोगों का छत्तीसगढ़ की भाषा और संस्कृति से परिचय कराया जाए, इस दिशा में छत्तीसगढ़ी भाषा में पाठ्यक्रम की शुरुआत इस विश्वविद्यालय ने की है यह सराहनीय कदम है। इस विश्वविद्यालय का अध्ययन-अध्यापन के साथ यह भी दायित्व बनता है कि छत्तीसगढ़ अंचल के भाषा, संस्कृति को समृद्ध करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर मुख्यमंत्री श्री साय ने समारोह में उपस्थित जनों से ''एक पेड़ माँ के नाम अभियान'' से जुड़ने की अपील की और कहा कि अपने आसपास सुलभ स्थान देखकर आप सभी एक पेड़ माँ के नाम जरुर लगाएं और उसकी देखरेख करें।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने गुजरात के मुख्यमंत्री पटेल से की मुलाकात

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने गांधीनगर में स्वर्णिम संकुल-2 में टेक्नोलॉजी के प्रयोग का किया अध्ययन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज अपने गुजरात प्रवास के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से सीएम सचिवालय में मुलाकात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की तरफ से शुभकामनाएं दीं और उन्हें छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे योजनाओ की जानकारी दी।उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए बनाई जा रही महतारी सदन योजना की विस्तार से जानकारी दी। यह योजना विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके कल्याण के लिए बनाई गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस योजना की सराहना की और इसे एक आदर्श पहल बताया। उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को इस योजना का अध्ययन करने और इसे गुजरात में भी लागू करने की संभावनाओं पर विचार करने के निर्देश दिए। उसके पश्चात उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने पूर्व में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हुई मुलाकात में सीएम डैशबोर्ड के सबंध में हुई चर्चा एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार गुजरात राज्य के सीएम डैशबोर्ड का अवलोकन किया। स्वर्णिम संकुल 2, जनसंपर्क इकाई, मुख्यमंत्री सचिवालय में उन्होंने टेक्नोलॉजी के प्रयोग से विभिन्न आवेदनों के निगरानी व निराकरण प्रयोगों का अध्ययन किया। स्वर्णिम संकुल 2 में उपमुख्यमंत्री ने टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी प्रणाली का निरीक्षण किया और इस प्रणाली की कार्यप्रणाली को समझा। इस अवसर पर चिप्स (छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी) के सीईओ रितेश अग्रवाल और चिप्स की टेक्निकल टीम भी उपस्थित थी। गुजरात की टीम ने उपमुख्यमंत्री को टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी की कार्यप्रणाली और इसके प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने टेक्नोलॉजी के प्रयोग से आवेदनों के त्वरित और प्रभावी निराकरण की सराहना की। उन्होंने कहा, ''टेक्नोलॉजी का सही उपयोग प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रणाली नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान में सहायक साबित होगी। गुजरात के टेक्नोलॉजी टीम ने बताया कि इस प्रणाली के माध्यम से आवेदनों की निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है। यह प्रणाली नागरिकों को अपनी शिकायतों और आवेदनों की स्थिति का ऑनलाइन ट्रैकिंग करने की सुविधा भी प्रदान करती है।

एनएसयूआई के आंदोलन बैन पर बोले रोहरा

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 36 गुटों में बटी

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री जगदीश (रामू) रोहरा ने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व द्वारा अपने ही छात्र संगठन एन.एस.यू.आई. के आंदोलन-प्रदर्शन पर पाबंदी लगाए जाने को कांग्रेस मचे घमासान और उसके विभिन्न सहयोगी संगठनों की दिशाहीनता का जीवंत प्रमाण निरुपित किया है। श्री रोहरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस न केवल मुद्दाविहीन और वैचारिक तौर पर दिशाहीन नजर आ रही है, अपितु कांग्रेस में आज कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। नतीजतन कांग्रेस में नेतृत्व के नाम पर गुटबाजी बढ़ रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री रोहरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में 36 गुट हैं और नेता व कार्यकर्ता एक-दूसरे पर आरोप मढ़कर अपमानित करने भी बाज नहीं आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्लीपर सेल कह देते हैं तो कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता उनके खिलाफ बेहिचक मोर्चा खोल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद बघेल समेत बड़े नेताओं पर की गई टिप्पणियों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री की हुई छीछालेदर को प्रदेश भूला नहीं है। श्री रोहरा ने कहा कि इतना सब होने के बावजूद कांग्रेस इन सारे घटनाक्रमों से कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। गुटबाजी और मनमानियों ने कांग्रेस के संगठनात्मक ढाँचे को चरमरा कर रख दिया है और नौबत अब अपने ही छात्र संगठन के आंदोलन-प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने की आ गई है। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री रोहरा ने कहा कि कांग्रेस व उसके सहयोगी संगठनों का आलम यह है कि हर जिले में नेता एक-दूसरे की शिकायत कर रहे हैं, कोई प्रदेश का प्रभारी कांग्रेस में टिक नहीं रहा है और अब एनएसयूआई पर आंदोलन करने पर बैन लगाया गया है। श्री रोहरा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यहां नेता प्रतिपक्ष तो चरणदास महंत हैं, लेकिन बयानबाजी कोई और करता रहता है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की अंतर्कलह के इस दौर में कौन-से गुट को राहुल गांधी का आशीर्वाद मिलता है।

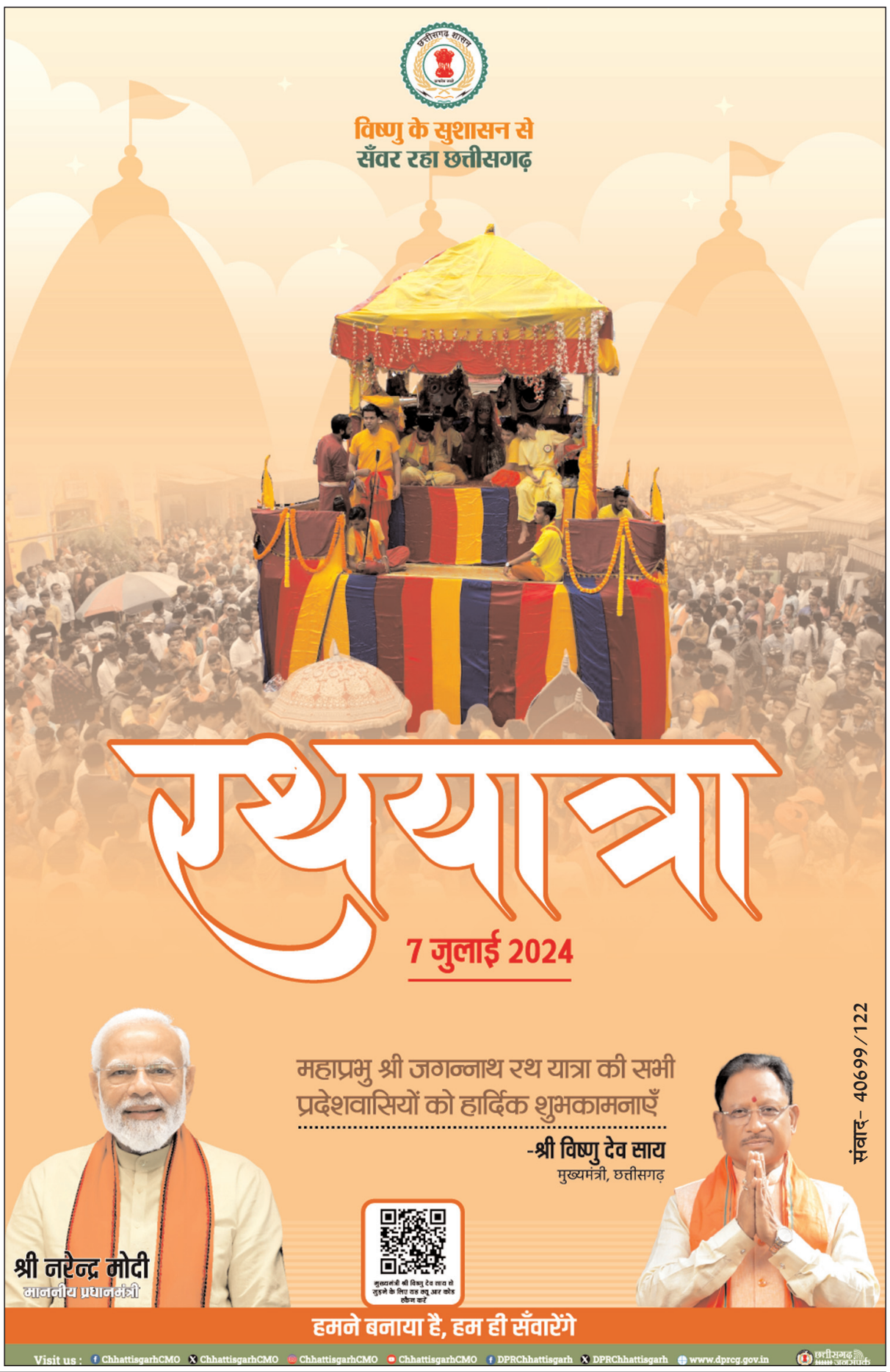

श्याम प्रसाद ने भारत की अखंडता के लिए अपना सब कुछ त्यागाःकिरण

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को पूरे प्रदेश में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जयंती (06 जुलाई) पर विभिन्न कार्यक्रम रखकर उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण किया और उनके बताए मार्ग पर चलकर शक्तिशाली, समृद्धशाली और स्वाभिमानी भारत के संकल्प को पूर्ण करने की प्रतिबद्धता दुहराई।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक किरण सिंह देव ने बस्तर जिले के सुदूर क्षेत्र दरभा मण्डल के कामानार ग्राम में शनिवार को भाजपा के ग्रामीण कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाकर उनको याद किया और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर श्री देव ने डॉ. मुखर्जी के छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में भाजपा केंद्र सहित अनेक राज्यों में सत्तासीन है जो हमारे महापुरुषों की तपस्या व बलिदान के कारण ही संभव हो पाया है। डॉ. मुखर्जी के आदर्शों को अपनाकर उनके विचारों को साकार रूप प्रदान करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि अगर देश के पास भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो कश्मीर का विषय चर्चा में नहीं आता । जिस प्रकार लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने खंड-खंड हो रहे देश को अखंड बनाया, उसी प्रकार डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अखंड भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए अपना पूरा जीवन होम कर दिया। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे। उनके जीवन से ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को सीख लेनी चाहिए। उनका स्वयं का जीवन प्रेरणादायी, अनुशासित तथा निष्कलंक था। राजनीति उनके लिए राष्ट्र की सेवा का साधन थी, उनके लिए सत्ता केवल सुख के लिए नहीं थी।

अखण्ड भारत की परिकल्पना के सूत्रधारों में पं.श्यामा प्रसाद मुखर्जी अग्रणी : बृजमोहन

भाजपा ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती संगठन महापर्व की तरह मनाया पूरे सप्ताह होंगे कार्यक्रम

रायपुर. 6 जुलाई शनिवार को महान शिक्षाविद्, चिन्तक,विचारक एवं भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर्ष के साथ मनाई जाती है , इस अवसर पर भाजपा द्वारा संगठन आधारित विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है पूरे देश में पंडित मुखर्जी की जयंती विशेष तौर पर मनाई जाती है इसी कड़ी में भाजपा रायपुर शहर जिला द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

अलग अलग कार्यक्रमों में भाजपा के वरिष्ठ नेता गण रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री केदार कश्यप, विधायक गण राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित रहे इसी तिथि से भाजपा का संगठन पर्व प्रारंभ होने जा रहा है जिसके तहत पूरे सप्ताह विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे जिसे हम हर्षोल्लास के साथ पार्टी में नए कार्यकर्ताओं को जोड़कर संगठन को और मजबूत करेंगे। भाजपा रायपुर जिला द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया प्रातः 10:00 बजे- श्यामा प्रसाद मुखर्जी शारदा चौक पर उनकी प्रतिमा में माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें स्मरण किया गया ।

प्रातः 11:00 बजे-जिला कार्यालय एकात्म परिसर में तैलचित्र पर माल्यार्पण,पुष्पांजलि अर्पित की गई एवं उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर विस्तृत उद्बोधन रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल और वरिष्ठ भाजपा नेता सच्चिदानंद उपासने ने कार्यकर्ताओ को दिया. रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस अवसर पर कार्यकर्ताओ को संबोधित करते हुए कहा की राष्ट्रोत्थान व सेवा भाव को आधार बनाकर भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले परम श्रद्धेय डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर उन्हें हम सभी की ओर से कोटि कोटि नमन , समतामूलक समाज व अखंड भारत की संकल्पना के पोषक आपके विचार आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अत्यंत अनुसरणीय हैं एवं कालांतर तक उनका अनुसरण कर हम मां भारती के वैभव को वैश्विक पटल पर उदयीमान करने अपना सम्पूर्ण योगदान देते रहेंगे ।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.